www.deshkiupasana.com
राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र
RNI NO - UPHIN/2022/86937
जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE
सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 202 | जौनपुर मंगलवार, 10 मार्च 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रुपये

संक्षिप्त खबरें

दिल्ली–एनसीआर में मार्च की शुरुआत से ही चढ़ा पारा

नोएडा, (एजेंसी)। दिल्ली–एनसीआर में मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी का असर तेजी से बढ़ने लगा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 37 से 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। आसमान में आंशिक बादल छाए रहने का अनुमान है, फिलहाल किसी तरह की मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 9 मार्च को अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इस दिन दिन के समय आर्द्रता करीब 35 प्रतिशत और सुबह के समय 85 प्रतिशत तक रह सकती है। इसी तरह 10 मार्च को अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम 18 डिग्री रहने का अनुमान है, जबकि आर्द्रता 40 से 90 प्रतिशत के बीच रह सकती है। वहीं 11 मार्च को अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई गई है।इन दिनों आसमान में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। गर्मी के साथ–साथ वायु प्रदूषण भी लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। अलिपुर में एक्यूआई 243, आनंद विहार में 239, अशोक विहार में 233 और बवाना में 273 दर्ज किया गया।

पंजाब बजट पर भाजपा का हमला – महिलाओं संग बड़ा धोखा

चंडीगढ़, (एजेंसी)। पंजाब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने पंजाब के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट पंजाब की माताओं–बहनों के साथ बड़ा धोखा है और किसानों, कर्मचारियों, आम जनता को निराश करने वाला है।श्री शर्मा ने रविवार को यहां कहा कि 16 मार्च 2022 को बनी आम आदमी पार्टी की सरकार के चार वर्ष यानी 48 महीने पूरे होने जा रहे हैं। यदि भगवंत मान सरकार वास्तव में महिलाओं के प्रति संवेदनशील होती, तो उन्हें 1000 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से पिछले चार वर्षों के 48 हजार रुपये एकमुश्त देने का प्रावधान बजट में करती।श्री शर्मा ने कहा कि सरकार ने 1000 या 1500 रुपये देने की घोषणा तो की है, लेकिन इसके लिए पूरा बजट भी नहीं रखा गया। इस योजना के लिए लगभग 15 हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता है, जबकि बजट में मात्र 9300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सरकार ने योजना के लिए पंजीकरण की शर्त लगा दी है। जिस तरह 10 लाख रुपये की स्वास्थ्य बीमा योजना का पंजीकरण अब तक पूरा नहीं हो पाया, उससे साफ है कि इस योजना का पंजीकरण भी लंबे समय तक लटका रहेगा और महिलाओं को लाभ नहीं मिल पाएगा।

शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल से बनेगा विकसित भारत : प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। बजट के बाद आयोजित वेबिनार श्रृंखला के चौथे सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि "सबका साथ, सबका विकास दृ जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति" केवल चर्चा का विषय नहीं, बल्कि सरकार का मूल ध्येय और संकल्प है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेल और संस्कृति जैसे मूलभूत क्षेत्र जन आकांक्षाओं को पूरा करने के बड़े माध्यम हैं। इसी उद्देश्य से बजट वेबिनार में इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर व्यापक चर्चा की जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, विद्वानों, उद्यमियों और युवाओं के सुझाव बजट घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज प्रिवेंटिव और होलिस्टिक हेल्थ के लिए एक बड़े विजन पर काम कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है और सैकड़ों जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं। आयुष्मान भारत योजना और आरोग्य मंदिरों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच गांव–गांव तक बढ़ी है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में देश में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या तेजी से बढ़ेगी और दुनिया के कई देशों में केयरगिवर्स की मांग भी बढ़ रही है। ऐसे में हेल्थ सेक्टर में युवाओं के लिए स्किल आधारित रोजगार के नए अवसर तैयार हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने विशेषज्ञों से नए ट्रेनिंग मॉडल और साझेदारी विकसित करने के सुझाव देने का आग्रह किया। पीएम मोदी ने टेली–मेडिसिन को भी स्वास्थ्य सेवाओं का अहम माध्यम बताते हुए कहा कि दूर–दराज के क्षेत्रों के लोग बड़ी संख्या में इसका लाभ उठा रहे हैं और इस पर भरोसा

बढ़ रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में अभी भी जागरूकता और सहजता बढ़ाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में देश के युवाओं के माइंडसेट में बड़ा बदलाव आया है। आज गांव, कस्बों और शहरों से आगे बढ़कर हर युवा कुछ नया करने का सपना देख रहा है। उन्होंने कहा कि इस नई सोच को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा प्रणाली को लगातार आधुनिक और अपडेट रखना होगा। नई शिक्षा नीति ने इसके लिए मजबूत आधार तैयार किया है। अब जरूरी है कि पाठ्यक्रम बाजार की जरूरतों के अनुसार अपडेट हों और शिक्षा प्रणाली को रियल वर्ल्ड इकॉनमी से तेजी से जोड़ा जाए। उन्होंने ।ए ऑटोमेशन, डिजिटल इकॉनमी और डिजाइन ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों पर विशेष फोकस बढ़ाने की आवश्यकता बताई। नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में शिक्षा को रोजगार और उद्यमिता से जोड़ने के लिए लगातार काम हो रहा है। यूनिवर्सिटी टाउनशिप जैसे नए मॉडल इसी सोच को आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि भारत एवीजीसी सेक्टर यानी एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स को बढ़ावा दे रहा है और देश इनोवेशन आधारित अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने शिक्षाविदों से आग्रह किया कि वे अपने कैंपस को इंडस्ट्री कोलैबोरेशन और रिसर्च ड्रिवन लर्निंग का केंद्र बनाने पर विचार करें, ताकि छात्रों को रियल वर्ल्ड एक्सपोजर मिल सके। पीएम मोदी ने कहा कि विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित यानी ज्स्ड क्षेत्रों में बेटियों की रुचि लगातार बढ़ रही है, जो गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि भविष्य की तकनीकों के दौर में यह सुनिश्चित करना होगा कि अवसरों की कमी के कारण कोई भी बेटी पीछे न रह जाए। उन्होंने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और ऐसा रिसर्च इकोसिस्टम विकसित करने पर जोर दिया, जहां युवा शोधकर्ताओं को नए प्रयोग और नवाचार करने के पर्याप्त अवसर मिलें। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा शक्ति तभी राष्ट्रीय शक्ति बनती है जब वह स्वस्थ, अनुशासित और आत्मविश्वासी हो। इसी कारण पिछले वर्षों में खेलों को राष्ट्रीय विकास की महत्वपूर्ण धारा के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया जैसी पहलों से देश में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को नई ऊर्जा मिली है और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने प्रतिभाओं की पहचान को बेहतर बनाने, खिलाड़ियों को संरचित आर्थिक सहायता देने और खेल संस्थाओं को अधिक प्रोफेशनल बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में देश में कॉमनवेल्थ गेम्स होने हैं और भारत ओलंपिक आयोजन के प्रयास में भी जुटा है। ऐसे में कम उम्र से ही प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें तराशना जरूरी है।

टी 20 विश्वकप जीतने पर राज्यसभा में भारतीय क्रिकेट टीम को दी गई बधाई

नई दिल्ली, (एजेंसी)। टी20 विश्व कप में मिली खिताबी जीत पर सोमवार को राज्यसभा में भारतीय टीम को बधाई दी गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने राज्यसभा सदस्यों की तरफ से विजेता भारतीय टीम को बधाई देते हुए जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यह देश के लिए गर्व की बात है कि भारतीय टीम ने आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप का खिताब जीत लिया है। तीसरी बार भारत ने टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया

भारतीय क्रिकेट टीम ने अहमदाबाद के नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में शानदार प्रदर्शन किया। यह तीसरी बार है जब भारत ने टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। दिलचस्प बात है कि लगातार दूसरी बार टीम ने ऐसा किया है क्योंकि भारत ने इससे पहले संस्करण में भी ट्रॉफी अपने नाम की थी। भारत पहला देश है जो अपनी मेजबानी में टी20 विश्व कप का विजेता बना राधाकृष्णन ने कहा कि यह जीत इसलिए भी विशेष है क्योंकि भारत पहला देश है जो अपनी मेजबानी में टी20 विश्व कप का विजेता बना है। पूरे टूर्नामेंट के दौरान टीम के शानदार प्रदर्शन ने देशभर के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को अपार खुशी और गर्व का अनुभव कराया है। सदन की ओर से शानदार उपलब्धि के लिए दी हार्दिक बधाई सदन की ओर से भारतीय टीम के खिलाड़ियों, सहयोगी स्टाफ और भारतीय क्रिकेट से जुड़े सभी लोगों को इस शानदार उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई। यह सदन उनकी आने वाले वर्षों में निरंतर सफलता की कामना करता है।

बहस नहीं, सिर्फ अराजकता फैलाने में रुचि- जेपी नड्डा

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सोमवार को पश्चिम एशिया संघर्ष पर विदेश मंत्री एस जयशंकर के संबोधन के दौरान विपक्ष द्वारा की गई नारेबाजी की निंदा करते हुए कहा कि विपक्ष को बहस करने में नहीं बल्कि केवल ष्अराजकता फैलानेष में दिलचस्पी है। विपक्ष पर ष्अपने फायदे के लिए राजनीति करनेष का आरोप लगाते हुए नड्डा ने कहा कि वे इसमें कभी सफल नहीं होंगे। राज्यसभा में नड्डा ने कहा कि अत्यंत दुख के साथ मैं कह रहा हूं कि विपक्ष का व्यवहार बेहद गैरजिम्मेदाराना और निंदनीय है। उन्हें न तो देश में कोई रुचि है और न ही बहस में, बल्कि उन्हें केवल अराजकता फैलाने में रुचि है। नड्डा ने आगे कहा कि उन्हें विकसित भारत, देश की प्रगति में कोई रुचि नहीं है, उनकी रुचि केवल अपने फायदे की राजनीति में है, जिसमें वे कभी सफल नहीं होंगे। जयशंकर ने

अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री उभरते घटनाक्रमों पर लगातार नजर रख रहे हैं और संबंधित मंत्रालय प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए समन्वय कर रहे हैं। यह घटनाक्रम 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमलों के बाद शुरू हुए युद्ध के मद्देनजर सामने आया है, जिसमें ईरान को निशाना बनाया गया था। इन हमलों में पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई और सत्तारूढ़ दल के कई प्रमुख सदस्यों की मौत हो गई थी। इसके बाद से स्थिति और बिगड़ गई है, सप्ताहांत में तेल भंडारों और जल विलवणीकरण संयंत्रों पर नए हमले हुए हैं। जयशंकर ने कहा कि सरकार ने क्षेत्रीय अस्थिरता को लेकर पहले ही अपनी आशंकाएं व्यक्त कर दी थीं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 20 फरवरी को एक बयान जारी कर गहरी चिंता व्यक्त की थी और सभी पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया था। हमारा मानना ध्है कि तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति का सहारा लेना चाहिए। संघर्ष की गंभीरता पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने पुष्टि की कि भारत ने 28 फरवरी, 2026 को आधिकारिक तौर पर युद्ध पर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने क्षेत्रों में तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति के आह्वान को दोहराया, साथ ही बढ़ते हताहतों और ईरानी नेतृत्व के पतन की ओर ध्यान आकर्षित किया।

संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण, पश्चिम एशिया के हालात पर घमासान के आसार

नई दिल्ली, (एजेंसी)। संसद के बजट सत्र का सोमवार से दूसरा चरण शुरू हो रहा है। इसके भी हंगामेदार रहने के आसार हैं। सत्र के पहले दिन लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने के लिए विपक्ष के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इसके लिए एनडीए और विपक्षी गठबंधन के दलों ने अपने सांसदों को उपस्थित रहने का व्हिप भी जारी किया है। हालांकि सरकार के संख्या बल के आधार पर विपक्ष का प्रस्ताव पारित होने की उम्मीद नहीं है। 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलने वाले इस दूसरे चरण में पश्चिम एशिया के संघर्ष से लेकर भारत–अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर भी पक्ष–विपक्ष में तकरार के आसार हैं। बजट सत्र के पहले चरण में 28 जनवरी से 13 फरवरी कार्यवाही चली थी।विपक्ष ईरान के खिलाफ अमेरिका–इस्राइल के संयुक्त हमले से पश्चिम एशिया में उपजे संकट और भारत–अमेरिका व्यापार समझौते को

लेकर सरकार को घेरने की भी तैयारी कर रहा है। वहीं, सत्ता पक्ष की ओर से बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान के मुद्दे को पूरे जोरशोर से उठाए जाने की संभावना है।बजट सत्र के पहले दिन सोमवार को लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद 118 विपक्षी सांसदों की तरफ से स्पीकर को हटाने संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी। विपक्ष ने कार्यवाही संचालन में स्पीकर पर विपक्ष के अधिकारों का हनन करने का आरोप लगाया है। हालांकि, सरकार के पास 290 से अधिक सांसदों के समर्थन के कारण प्रस्ताव के पारित होने की उम्मीद नहीं है।सरकार स्पीकर को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव पर बेहद कड़ा रुख अपनाने की तैयारी में है। चर्चा में भाग लेने वाले सांसद और मंत्री कांग्रेस के संसदीय परंपराएं तोड़ने को मुद्दा बनाएंगे। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति के अपमान के मामले में सरकार के रुख को देखते हुए तय माना जा रहा है कि इसे बड़ा मुद्दा बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मुद्दे पर ममता बनर्जी सरकार की तीखी आलोचना कर चुके हैं। ऐसे में बजट सत्र का दूसरा चरण भी पहले चरण की तरह ही सरकार और विपक्ष के बीच वार–पलटवार का गवाह बन सकता है।विपक्षी दलों का आरोप है कि उन्हें बहस के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया जाता और उनके नोटिसों को पक्षपातपूर्ण तरीके से स्वीकार नहीं किया जाता।

स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, किरेन रिजिजू ने संभाला मोर्चा

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करेंगे। विपक्ष ने ओम बिरला पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया है। 118 विपक्षी सांसदों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को कथित तौर पर बोलने नहीं दिए जाने के बाद अध्यक्ष के पक्षपातपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया गया है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर, निशिकांत दुबे, रवि शंकर प्रसाद और भर्तृहरि महताब इस विषय पर अपनी बात रखेंगे। सूत्रों के अनुसार, लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के चिराग पासवान भी सत्र को संबोधित करेंगे। इससे पहले दिन में, किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए चेतावनी दी कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर उन्हें पछतावा होगा। पत्रकारों को संबोधित करते हुए रिजिजू ने स्पीकर का बचाव करते हुए कहा कि यह प्रस्ताव बिना किसी कारण के और केवल एक व्यक्ति की हठधर्मिता को संतुष्ट करने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सदन में इसका करारा जवाब देने के लिए तैयार है और प्रस्ताव की हार की भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि संसद के बजट सत्र का दूसरा भाग आज से शुरू होने वाला है। दुख की बात है कि इसकी शुरुआत लोकसभा स्पीकर के खिलाफ विपक्ष, विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी द्वारा उन्हें हटाने के लिए लाए गए प्रस्ताव से हो रही है। हम इसका जवाब देंगे, लेकिन कांग्रेस को यह सोचना चाहिए कि संवैधानिक पदों और संवैधानिक गरिमा को कमजोर करने के लिए वे कितनी हद तक जा सकते हैं।

पंजाब की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, मान हर महीने देगी 1,000 रुपये

पंजाब, (एजेंसी)। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपना एक प्रमुख चुनावी वादा पूरा कर दिया है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने 2026–27 के बजट में मुख्यमंत्री महिला–ध्यान सत्कार योजना का एलान किया। इस योजना के तहत राज्य की 18 साल से ऊपर की लगभग सभी महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। सरकार का दावा है कि इस योजना के दायरे में राज्य की 97 प्रतिशत महिलाएं आएंगी। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो महिलाएं पहले से बुढ़ापा, विधवा या विकलांगता पेंशन ले रही हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। विशेष रूप से अनुसूचित जाति की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये दिए जाएंगे। हालांकि, सरकारी कर्मचारी (वर्तमान या पूर्व), आयकर देने वाले परिवार और वर्तमान या पूर्व सांसद–विधायक इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। वित्त मंत्री ने इसे दुनिया की पहली श्यूनिवर्सल कैश ट्रांसफरश स्कीम बताया है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। पंजाब में 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं की संख्या लगभग 1 करोड़ से ज्यादा है। इस योजना को लागू करने पर सरकार को हर साल करीब 10,000 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। विपक्ष ने इस योजना के समय पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार पिछले चार सालों से इस वादे को टाल रही थी।

अयोध्या में बाल विवाह पर प्रशासन सख्ती दिखाते हुए 14 वर्षीय लड़की और 18 वर्षीय लड़के की शादी ऐन वक्त पर रुकवाई

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या।सोमवार को जिले के थाना पूराकलंदर क्षेत्र में एक नाबालिग जोड़े का विवाह प्रशासन ने समय रहते रुकवा दिया।इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस और महिला आयोग की टीम महिला थानाध्यक्ष आशा शुक्ला व अन्य पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचकर बारात को रोककर दोनों पक्षों को चौकी बुलाया।छानबीन में सामने यह आया कि दुल्हन की उम्र मात्र 14 वर्ष और दूल्हे की उम्र 18 वर्ष है।जिसके चलते विवाह को अवैध मानते हुए तत्काल रोक दिया गया। किसके चलते बारात बैरंग लौटनी पडी।प्राप्त जानकारी के अनुसार, बारात पूराकलंदर थाना क्षेत्र के पलिया गांव की ओर जा रही थी।किसी जागरूक व्यक्ति ने प्रशासन को सूचना दी कि विवाह होने जा रहा जोड़ा नाबालिग है।सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और बाल संरक्षण से जुड़े अधिकारियों की टीम सक्रिय हो गई और बारात को बीच रास्ते में ही रोक लिया गया।जब पुलिस ने दोनों परिवारों से दूल्हा–दुल्हन की उम्र से संबंधित दस्तावेज मांगे,तो पता चला कि लड़की अभी 14 वर्ष की है और लड़का भी 18 वर्ष का है।भारत में बाल विवाह निषेध कानून के अनुसार लड़की की शादी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष निर्धारित है।ऐसे में यह विवाह कानूनन अपराध की श्रेणी

में आता है।प्रशासन ने दोनों परिवारों को पूराकलंदर पुलिस चौकी बुलाया। यहां समझाइश के बाद दोनों पक्षों से लिखित सहमति पत्र लिया गया कि जब तक लड़का–लड़की बालिग नहीं हो जाते, तब तक उनका विवाह नहीं कराया जाएगा। इसके बाद बारात को वापस भेज दिया गया।मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य महिला आयोग की एक सदस्य भी मौके पर पहुंचीं और परिवारों को बाल विवाह के दुष्परिणामों तथा कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी।उन्होंने कहा कि बाल विवाह न केवल कानूनन अपराध है बल्कि इससे बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य पर भी गंभीर असर पड़ता है।अधिकारियों ने ग्रामीणों से अपील की कि यदि कहीं बाल विवाह की जानकारी मिले तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें।प्रशासन का कहना है कि ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके।समय रहते प्रशासन की सक्रियता से एक नाबालिग जोड़े का विवाह रुक गया और दोनों परिवारों को कानून की जानकारी देकर बालिग होने तक शादी न करने की लिखित सहमति ली गई।

संपादकीय

ट्रंप के मूड की तलवार

इस दौर में अमेरिका के साथ हुए हर समझौते के टिकाऊपन पर हमेशा राष्ट्रपति ट्रंप के मूड की तलवार लटकी रहती है। फिर अमेरिका के भीतर स्थितियां अस्थिर हैं। ट्रंप के कदमों पर वहां राजनीतिक आम सहमति नहीं है। अमेरिका ने अब भारत से सौर ऊर्जा से संबंधित पाट–पुर्जों के आयात पर 126 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है। इसे भारत के फूलते–फलते सौर उद्योग पर घातक प्रहार समझा गया है। डॉनल्ड ट्रंप प्रशासन ने ये कदम उस समय उठाया, जब अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टैरिफ वॉर के स्वरूप को लेकर अनिश्चय है। ट्रंप ने जिस कानून के तहत दंडात्मक आयात शुल्क लगाए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसे अवैध ठहरा दिया। उसके बाद ट्रंप ने दूसरे कानून के तहत सभी देशों पर दस फीसदी टैरिफ लगाया। बाद में कहा गया कि वे इसे 15 फीसदी तक ले जाएंगे। अब बताया गया है कि आम टैरिफ 10 फीसदी रहेगा और ट्रंप बाकी पांच फीसदी का इस्तेमाल विभिन्न देशों के रुख के हिसाब से करेंगे। इस बीच अलग–अलग उत्पादों (मसलन स्टील) पर लगाए गए शुल्क जारी रहेंगे और नए शुल्क भी ट्रंप लगाते रहेंगे, जैसाकि अब उन्होंने सौर ऊर्जा से संबंधित पाट–पुर्जों पर लगाया है। ऐसे में भारत सहित हर देश के सामने यह प्रश्न है कि ट्रंप प्रशासन से द्विपक्षीय व्यापार समझौता करने का क्या औचित्य है? किसी समझौते के तहत हुई लेनदेन से देश के अधिकांश उद्योगों और अर्थव्यवस्था के ज्यादातर क्षेत्रों को लाभ ना हो रहा हो, तो वैसा समझौता करने की ललक क्यों दिखाई जानी चाहिए? मुद्दा यह भी है कि इस दौर में अमेरिका के साथ हुए समझौते के टिकाऊपन पर हमेशा ट्रंप के मूड की तलवार लटकी रहती है। फिर अमेरिका के भीतर स्थितियां अस्थिर हैं। ट्रंप जो कर रहे हैं, उस पर वहां राजनीतिक आम सहमति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय जाहिर हुआ है कि शासन की सभी संस्थाओं के बीच उन कदमों की वैधानिकता पर आम समझ का अभाव है। इसलिए भारत सरकार को ताजा स्थितियों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। अभी भी समय है कि वह पहले इस बारे में देश को भरोसे में ले और राजनीतिक आम सहमति तैयार करे। वरना, समझौते के प्रति उसके उत्साह पर सवाल उठते रहेंगे। उसे याद रखना चाहिए कि ट्रंप के हर मूडी एक्शन के साथ ऐसे सवाल और संगीन होते जाएंगे।

इसराइल और अमेरिका की निंदा

अजय दीक्षित

विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सैन्य क्षमता के देश अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने जैसे पूरी दुनिया, विशेषकर मध्य पूर्व एशिया को युद्ध की आग में झोंककर तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। इसराइल ने 28 फरवरी को अमेरिका के साथ मिलकर ईरान में मिसाइलों, बम वर्षक विमानों से एक साथ हमला कर ईरान के सुप्रीम कमांडर अली खुमेनई सहित, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री,43 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। विगत तीन दिन से इसराइल और ईरान में घमासान मचा हुआ है। दूसरी ओर ईरान ने दुबई, कुवैत, यमन, दोहा, जद्दा, बहरीन, आबुधाबी में स्थित अमेरिका के ठिकानों पर हमला कर दिया। दुनियां भर में इसराइल और अमेरिका के इस कृत्य की निंदा हो रही है। यहां तक कि पाकिस्तान और भारत में भी कई शहरों लोगों ने विरोध जताया है। हालांकि भारत आधिकारिक तौर पर विश्व शांति की अपील की है। इस घटनाक्रम का विश्व बाजार पर गहरा असर पड़ेगा। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेगी क्योंकि पूरे विश्व का 22 फीसदी क्रूड ऑयल भंडार ईरान पर है और भारत अपनी जरूरत का तीस फीसदी तेल ईरान से खरीदता है।ईरान ने मिसाइलों से दुबई, कुवैत, यमन, दोहा, जद्दा, बहरीन आबुधाबी,के तेल संयंत्रों को बर्बाद कर दिया है। आज बाजार खुलते ही सेंसेक्स 1000 पॉइंट नीचे गिर गया। दरअसल जब से 2025 से दूसरी बार यू एस प्रेसिडेंट बने हैं डोनाल्ड ट्रंप तब उनके फैसलों में आग निकल रही है। पहले उन्होंने टैरिफ बार खेला और भारत , चाइना को इस जाल में फंसा कर अपनी बात मनवाई।इस वर्ष उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को पकड़कर अमेरिकी जेल में डाल दिया और वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया। ईरान पर आठ माह पूर्व उसके परमाणु हथियारों के ठिकानों पर हमला किया। बस रूस ही ऐसा देश है जो अमेरिकी दबाब में नहीं आ रहा है और वह भी यूक्रेन को हड़प रहा है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इतना नहीं नाटो देश भी अब अमेरिका के साथ है। जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड ने अपनी सेना युद्ध में उतारने का मन बना लिया है। डॉनल्ड ट्रंप से पहले के यू एस प्रेसिडेंट चाहे वह बराक ओबामा रहे हो या जोए बाइडन, यहां तक कि जॉर्ज बुश,सीनियर,जूनियर, विश्व राजनीतिक दखल तो रखते हुए सौम्यता बनाए रखते थे।हालांकि 50 वर्षों में मध्य पूर्व एशिया में अमेरिका ने सऊदी अरब, कुवैत, यमन, दोहा जद्दा, बहरीन, आबुधाबी को अपने रखा कवच में रखा है और वहां पर अमेरिका के सैनिक अड्डे, हवाई जहाज है। लेकिन इसराइल को उन्होंने विशेष रूप से सृजित किया है। इसराइल के पास आज ईरान,इराक,जैसे बड़े से अधिक सैन्य क्षमता है। यह सब अमेरिका का किया धारा है।ईरान भी कट्टर मुस्लिम शिया देश है जबकि साउथ एशिया में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यूएई, सऊदी अरब, कुवैत यमन दोहा जद्दा बहरीन आबुधाबी,सभी सुन्नी मुस्लिम देश है।ईरान को केवल लेबनान, बेरुत से सहयोग मिलता है।इसी लिए उसने हिज्बुल्लाह,हमास, अलकायदा, तालिबान, मिलेशिया को पनपा रखा है। ईरान का इतिहास भी कम रक्त रंजित नहीं है।यहां भी 1979 से पहले राजा पहलवी की किंग डम थी लेकिन अयातुल्ला खोमानी नामक कट्टर पंथी ने इस्लामिक क्रांति कर दी और ईरान का खुला पन जाता रहा है महिलाओं पर बेहद कड़े कानून लागू हुए ।1989 में अयातुल्ला खोमानी की निधन के बाद से 37 वर्ष से अली खुमेनई का शासन है। ईरान इसराइल से निपटने के लिए परमाणु हथियारों को हासिल करना चाहता था उसने 90 फीसदी तक यूरेनियम का परिशोधन कर लिया था। लेकिन अमेरिका ने अगस्त 2025 में उनका परमाणु हथियार बनाने वाला स्थान पर बमबारी की । दरअसल सऊदी अरब कुवैत यमन दोहा जद्दा बहरीन आबुधाबी, सभी चाहते हैं कि ईरान मध्य पूर्व में मुस्लिम देशों का नेता बनना चाहता है। ईरान के पूरे विश्व का 22 फीसदी क्रूड ऑयल भंडार है जो वेनेजुएला के बाद दूसरे स्थान पर है। डॉनल्ड ट्रंप ने ईरान को दबाने की मोहिम तो अपने पहले कार्यकाल से चला रखी है लेकिन 2021 के चुनाव में वे जोए बाइडन से हार गए थे। लेकिन इस बार उन्होंने इसराइल से मिल कर ईरान पर कब्जा तो नहीं अपना उल्लू बैठाने का फैसला कर दिया था। और अमेरिका में रह रहे पहलवी बांसाज को सत्ता सौंपेगे।इसी लिए अमेरिका ने सबसे पहले अली खुमेनई को निपटाया है। सूत्र बताते हैं कि यह युद्ध अभी रुकने वाला नहीं है।लगे हाथ इजरायल ने भी गाजा पट्टी पलस्तीन खाली कराली है। पलस्तीनियों को अफ्रीकी देश में बसाने की मुहिम चल रही है।

गेमचेंजर होगी नेपाल में आरएसपी की शानदार जीत

नित्य चक्रवर्ती

राजनीति आरएसपी नेपाल की सबसे नई राजनीतिक पार्टियों में से एक है जो 2026 के चुनाव में मैदान में उतरी। आरएसपी की स्थापना 2022 में चुनाव से पहले हुई थी। पार्टी ने 131 चुनाव क्षेत्रों में चुनाव लड़ा और 10.7 प्रतिशत वोट हासिल किए, जिसमें सीधे चुनाव में 7 सीटें और समानुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत 13 सीटें जीतीं। पार्टी के प्रमुख बाबा लामचाने हैं, नेपाल में 5 मार्च को हुए आम चुनावों में जेनजेड समर्थित राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) की शानदार जीत न सिर्फ इस छोटे से हिमालयी देश के राजनीतिक इतिहास में बल्कि दक्षिण एशिया की बदलती राजनीति में भी एक गेमचेंजर है। नेपाल अब दक्षिण एशिया का दूसरा देश है जो सितंबर 2025 के दूसरे हफ्ते में बगावत के जरिए एक पारंपरिक राजनीतिक पार्टी की सरकार को हटाने वाले युवा आंदोलन के समर्थन वाली सरकार की स्थापना देख रहा है। सिर्फ दक्षिण एशिया के एक और देश, श्रीलंका में, सितंबर 2024 में कमोबेश ऐसा ही नजारा देखने को मिला था, जब नेशनल पीपल्स पावर (एनपीपी) के नेता ने श्रीलंका की पारंपरिक राजनीतिक पार्टियों को हराकर राष्ट्रपति चुनाव जीता था, जिन्होंने दशकों तक इस द्वीप देश पर राज किया था। 2023 के श्रीलंका चुनाव, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ 2022 में छात्रों और लोगों के विद्रोह में सत्ताधारी सरकार के हटने के बाद हुए थे। दक्षिण एशिया के एक और देश, बांग्लादेश में, छात्रों के विद्रोह की वजह से अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार चली गई, लेकिन इस साल 12 फरवरी को हुए राष्ट्रीय चुनावों में युवाओं के नेतृत्व वाली कोई सरकार नहीं बनी। इसके विपरीत हसीना सरकार को हटाने के लिए विद्रोह के समर्थकों द्वारा बनाई गई पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा और पारंपरिक पार्टी बीएनपी को दो–तिहाई मतों से जीत मिली। इसलिए बांग्लादेश परिवर्तन के बस से चूक गया जबकि श्रीलंका और नेपाल सफल रहे।नेपाल चुनावों के अंतिम नतीजे अभी नहीं आए हैं, लेकिन रुझानों से पता चलता है कि आरएसपी कुल 165 सीटों में से 100 सीटें पार करने वाली है, जिन पर सीधे चुनाव हुए थे। दूसरी पार्टियां गगन थापा के नेतृत्व वाली नेपाल कांग्रेस, पूर्व प्रधानमंत्री केपीएस ओली के नेतृत्व वाली सीपीएन(यूएमएल)और प्रचंड के नेतृत्व वाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) दो अंकों को छूने के लिए संघर्ष कर रही हैं। संकेत हैं कि आरएसपी, किसी दूसरी पार्टी पर निर्भर हुए बिना, अपने दम पर नई सरकार बना पाएगी। पिछले दो दशकों के संसदीय लोकतंत्र में अब तक नेपाल में किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास अकेले बहुमत नहीं रहने का रूझान यह रहा है। सरकार चलाने के लिए चुनाव के बाद गठबंधन बनाया गया था। सहयोगी कई बार बदले, जिससे मंत्रिमंडल गिर गया और फिर सत्ता में बने रहने के लिए एक नया गठबंधन बना। यह रूझान 2026 के चुनाव से बंद हो रहा है।आरएसपी नेपाल की सबसे नई राजनीतिक पार्टियों में से एक है जो 2026 के चुनाव में मैदान में उतरी। आरएसपी की स्थापना 2022 में चुनाव से पहले हुई थी। पार्टी ने 131 चुनाव क्षेत्रों में चुनाव लड़ा और 10.7 प्रतिशत वोट हासिल किए, जिसमें सीधे चुनाव में 7 सीटें और समानुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत 13 सीटें जीतीं। पार्टी के प्रमुख बाबा लामचाने हैं, जो एक मीडिया मालिक हैं। काठमांडू के पूर्व मेयर बालेंद्र शाह बाद में आरएसपी में शामिल हुए और 2026 में पूर्व प्रधानमंत्री के पीएस ओली को हराकर चुनाव जीते। वह इतने लोकप्रिय हैं कि उन्हें आरएसपी सरकार का अगला प्रधानमंत्री बनने के लिए चुना जा रहा है। वह नेपाल सरकार की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की, शाह और जेनजेड आन्दोलन के वरीय नेताओं के करीबी हैं। बालेंद्र शाह ने जेनजेड के संरक्षक के तौर पर काम किया। असल में, एक समय पर जेनजेड के अपनी पार्टी बनाने

पर भी कुछ चर्चा हुई थी, लेकिन आखिर में, वे शाह और आरएसपी के साथ आ गए।नेपाल में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने के सरकारी आदेश के विरोध में जेनजेड ने स्कूली छात्रों के साथ मिलकर आंदोलन शुरू किया था। फिर यह आंदोलन सत्ताधारी केपीएस ओली सरकार और सभी स्थापित राजनीतिक पार्टियों के पूरे विरोध में बदल गया। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुईं लेकिन नेपाली सेना ने सावधानी बरती। स्थिति काबू से बाहर होने के बाद, नेपाली सेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री ओली को पद छोड़ने के लिए कहा। उन्होंने और उनकी सरकार ने इस्तीफा दे दिया। सेना प्रमुख ने जेनजेड नेताओं और सिविल सोसाइटी नेताओं से सलाह करके पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनाने में मदद की।नेपाल की संसद के निचले सदन में 275 सीटें हैं। इसमें से 165 सीटें सीधे चुनाव के लिए हैं और बाकी 110 सीटें समानुपातिक प्रतिनिधित्व से भरी जाएंगी। नेपाल में सभी बड़ी पार्टियां सभी सीटों पर चुनाव लड़ती हैं और चुनाव के बाद जब उनकी ताकत का पता चलता है, तो पार्टियां गठबंधन करती हैं। इसी तरह, हटाए गए प्रधानमंत्री 73 साल के केपीएस ओली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (यूनिफाइडमार्क्सिस्टलेनिनिस्ट) सीपीआईएन (यूएमएल) का नेतृत्व कर रहे हैं। सितंबर में हटाए जाने से पहले वह नेपाली कांग्रेस के साथ गठबंधन में थे। एक और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल, जिन्हें प्रचंड के नाम से जाना जाता है, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख हैं। वह दूसरे कम्युनिस्ट गुटों को अपने साथ लाने में कामयाब रहे हैं। वह ओली के लिए मुख्य चुनौती देने वाले बनकर उभरे हैं।जहां दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों ने अपने पुराने नेताओं को बनाए रखा है, वहीं देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी नेपाली कांग्रेस ने जनुआ में एक युवा गगन थापा को अपना नया नेता चुना है। इस साल 49 साल के लोकप्रिय नेता ने 79 साल के पुराने शेर बहादुर देउबा की जगह ली है, जो 2006 के बाद लोकतंत्र शुरू होने के समय से पिछले दो दशकों में अलग–अलग गठबंधनों में पांच बार प्रधानमंत्री रहे। 35 साल के बालेंद्र शाह एक इंजीनियर और रैपर हैं। काठमांडू के मेयर के तौर पर अपने समय में उन्होंने बहुत अच्छी छवि बनाई। उन्हें भ्रष्टाचार की प्रथा के खिलाफ लड़ने वाले के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने आरएसपी के आस–पास कुछ सिविल राइट्स एक्टिविस्ट इकट्ठा किए हैं जो, अगर वह प्रधानमंत्री बनते हैं तो, उनके सलाहकार हो सकते हैं। बालेंद्र कुछ भारत–विरोधी टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं लेकिन वह एक समझदार इंसान हैं और विदेशियों के प्रति दुर्भावना से ग्रस्त नहीं हैं। उन्होंने एक इंडियन इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर किया है। उन्हें भारत–नेपाल सम्बंधों की अच्छी समझ है। यह देखा जाएगा कि नेपाल में नई सरकार के समय में द्विपक्षीय संबंध कैसे आगे बढ़ते हैं।

बजट सत्र का शेष हिस्सा प्रधानमंत्री के लिए और भारी

शकील

अब बजट सत्र का दूसरा हिस्सा आ गया। राहुल फिर लोकसभा में होंगे और जैसा कि उनका दावा है और वह हर बार सही साबित हो रहा है कि प्रधानमंत्री सदन में मेरे सामने नहीं आ सकते। अब जब अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर दिया है भारत की सारी तेल और गैस की आपूर्ति रुक गई है। और अमेरिका बहुत दया दिखाकर हमें 30 दिन के लिए रूस से तेल खरीदने की छूट दे रहा है प्रधानमंत्री मोदी के लिए संसद के बजट सत्र का पहला हिस्सा बहुत मुश्किल था। लेकिन दूसरा हिस्सा उससे भी ज्यादा मुश्किल होगा यह उन्होंने नहीं सोचा था।सोमवार 9 मार्च से दूसरा हिस्सा शुरू हो रहा है। विपक्ष जोश में है। पहले हिस्से के दौरान अमेरिका के साथ डील पर मोदी कुछ नहीं बोल सके। इसके अलावा उनके सबसे बड़े मुद्दे राष्ट्रवाद पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाणे की किताब के जरिए बड़ा हमला कर दिया। राहुल ने कहा कि जब चीनी टैंक अपनी पैदल सेना के साथ पूर्वी लद्दाख में हमारी सीमा में घुस रहे थे तो मोदी उन्हें रोकने का आदेश देने में असमर्थ साबित हुए। चीनी सीमा पर बिना प्रधानमंत्री से पूछे कोई कार्रवाई करने से मना कर रखा था।थल सेना अध्यक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर विदेश मंत्री सुरक्षा सलाहकार सबसे फोन करके, हाट लाइन पर कहते रहे कि पूछिए क्या करना है? करीब ढाई घंटे तक कुछ नहीं बताने के बाद आखिरी में प्रधानमंत्री का जवाब आया जो उचित समझो वह करो! देश में कमजोरी छुपाने के लिए यह मुहावरा बन गया। देश की सुरक्षा से समझौता! मगर प्रधानमंत्री ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। किया, सिर्फ यह कि लोकसभा में जहां उन्हें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देना था वहां आए ही नहीं। लोकसभा अध्यक्ष से कहलवा दिया कि विपक्ष की महिला सांसदों से खतरा! देश की सुरक्षा से समझौता और महिला सांसदों से डर!संसदीय इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव बिना प्रधानमंत्री या सदन के नेता के जवाब दिए पास करना पड़ा। अभी राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू कह रही हैं कि बंगाल जाने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (विपक्ष) ने उनका अपमान किया! भूल गईं कि अपमान तो एक महीने पहले प्रधानमंत्री ने उनके अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब न देकर किया था! लेकिन विपक्ष ने उस मामले में राष्ट्रपति का नाम जुड़ा होने के कारण अभिभाषण को मुद्दा नहीं बनाया और उसे पारित हो जाने दिया। सोचिए कि विपक्ष अगर उसे पास करने से इनकार कर देता तो राष्ट्रपति का कितना अपमान होता? मगर विपक्ष ने खुद को केवल प्रधानमंत्री तक ही सीमित रखा।प्रधानमंत्री के लिए बजट सत्र की शुरूआत ही मुश्किलों के साथ हुई। बजट में तो कुछ आम आदमी के लिए था ही नहीं। मगर अमेरिका ने बजट पेश होने के अगले दिन ही डील की घोषणा करके अपने यहां से बिना किसी शुल्क (टैरिफ) के जो कृषि उत्पाद भारत भेजे जाने हैं उसकी लिस्ट जारी कर दी। प्रधानमंत्री मोदी वादे कर रहे थे कि भारतीय बाजार विदेशों के कृषि उत्पाद के लिए नहीं खोला जाएगा। और यहां अमेरिका ने कह दिया कि उसके कृषि उत्पाद भारत जाएंगे भी और मोदी सरकार उन पर कोई टैरिफ भी नहीं लेगी। नेता प्रतिपक्ष राहुल ने इसे भारत के किसानों के साथ विश्वासघात बताया। डील पर मोदी बहुत बुरी तरह घिर गए। मगर यहां भी कोई जवाब नहीं दे पाए। राहुल गांधी ने लोकसभा में ही एपस्टीन फाइल का नाम लेकर यह और कह दिया कि उसकी वजह से ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री का मुंह बंद किए हुए है। नहीं तो भारत का कोई भी प्रधानमंत्री भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह करने वाली ऐसी डील नहीं करता। साथ ही यह भी कहा कि ट्रंप के एक हाथ में एपस्टीन फाइल है जिससे वह एक तरफ से गर्दन पकड़े है तो दूसरे हाथ में अडानी के क्रिमिनल मामलों के केस हैं इससे दूसरी तरफ से गर्दन दबा रहा है। न प्रधानमंत्री और न अडानी इन स्पष्ट आरोपों का जवाब दे पाए। और अब बजट सत्र का दूसरा हिस्सा आ गया। राहुल फिर लोकसभा में होंगे और जैसा कि उनका दावा है और वह हर बार सही साबित हो रहा है कि प्रधानमंत्री सदन में मेरे सामने नहीं आ सकते। अब जब अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर दिया है भारत की सारी तेल और गैस की आपूर्ति रुक गई है। और अमेरिका बहुत दया दिखाकर हमें 30 दिन के लिए रूस से तेल खरीदने की छूट दे रहा है तब संसद के बजट सत्र का दूसरा हिस्सा शुरू हो रहा है। मोदी जो हर मामले में बोलते हैं अमेरिका के मामले में एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं। पूरी तरह मौन हैं। बदनाम तो किया था सोच समझ कर बोलने वाले विद्वान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मौन मनमोहन बोल कर। मगर खुद तो केवल मौन ही नहीं हुए। ट्रंप के सामने हर मामले में मौन रहकर सहमति प्रकट करते हुए और दिख रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई की हत्या कर दी। लेकिन 6 दिन तक मोदी सरकार कोई प्रतिक्रिया तक व्यक्त नहीं कर पाई। लेकिन फिर जब कांग्रेस ने इसकी निंदा की। सोनिया और राहुल बोले तो भारत के विदेश सचिव ने ईरान दूतावास जाकर वहां शोक पुस्तिका में श्रद्धांजलि लिखी।अमेरिका का इतना डर। और यह डर अब सर्वव्यापी हो गया। डर भी छूत की बीमारी की तरह होता है। एक के होते ही तेजी से फैलने लगता है। सब में तो नहीं फैलता। जैसे राहुल पर डर का कोई असर नहीं है। मगर यह बात सबके लिए नहीं कही जा सकती। अभी सबने देख लिया कि नीतीश कुमार जिन्हें लोग प्रधानमंत्री मटेरियल बता रहे थे वे टिन पत्तर वाले मटेरियल निकले। ऐसे डरे, दबे कि मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा जाने को तैयार हो गए। खुद से लिखकर अपना मजाक उड़वा लिया कि राज्यसभा नहीं देखी थी वहां जाने की इच्छा है। पचासों उनके राज्यसभा में खड़े होकर बोले जाने वाले जवाब होंगे, दूरदर्शन के पास वीडियो होंगे कि जब वे केन्द्र सरकार में मंत्री थे कितनी बार राज्यसभा जाना होता था। नीतीश कुमार शायद भूल गए कि मंत्री दोनों सदनों में जा सकता है। जाता है। सदस्य वे लोकसभा के बने थे। मगर मंत्री दोनों सदनों में जवाबदेह होता है। जाना पड़ता है। जैसे मीडिया अब मोदी के मौन पर मौन है। वैसे ही नीतीश की बाडी लेंग्वेज पर भी। यूपीए के टाइम में कांग्रेस के नेताओं की बाडी लेंग्वेंज ही मीडिया पढ़ता रहता था। मगर अब यह विद्या विस्मृत हो गई है। नीतीश की तो बाडी लेंग्वेंज के साथ मानसिक अवस्था पर भी बात करना जरूरी थी। मगर सारा मीडिया जिसमें बिहार के कई योग्य पत्रकार भी शामिल हैं इस मामले में कुछ नहीं बता रहे। अगर कांग्रेस का या विपक्ष का कोई और मुख्यमंत्री होता तो उसकी ब्रेन रीडिंग भी यह कर देते और पूरे खानदान की भी। मगर यहां नीतीश की और जो उनके बेटे निशांत को बिहार में स्थापित करने की बात कही जा रही है उसकी राजनीतिक समझ की भी एक बात यह मीडिया नहीं करता है। संसद के सदनों के चाहे अंदर नहीं गूंजे मगर संसद सदस्यों के बीच तो यह मुद्दा सबसे हॉट टॉपिक रहेगा ही कि नीतीश का राजनीतिक कैरियर किस अपमानजनक तरीके से खत्म किया जा रहा है। सोमवार को पहले दिन ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इसके नोटिस पर टीएमसी ने साइन नहीं किए थे।

किफायती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं के लिए जनऔषधि परियोजना का रणनीतिक विकास

जगत प्रकाश नड्डा

जन औषधि सस्ती भी, भरोसेमंद भी, सेहत की बात, बचत के साथ

किसी राष्ट्र की प्रगति का असली पैमाना अक्सर इस बात से परिलक्षित होता है कि उसके नागरिक स्वास्थ्य सेवा जैसी बुनियादी आवश्यकताओं तक कितनी आसानी से पहुँच सकते हैं। दशकों तक, भारत के लाखों लोगों के स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए दवाओं की उच्च लागत एक प्रमुख वित्तीय बाधा रही है। इस संदर्भ में, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी), प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं को उनके ब्रांडेड समकक्षों की तुलना में काफी कम कीमत पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई पहल है। यह परियोजना सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल में एक महत्वपूर्ण कमी को दूर करके एक व्यापक और व्यवस्थित परिवर्तन लाने में सफल रही है। वैश्विक स्तर पर, जेनेरिक दवाइयाँ सुलभ स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों की मूलभूत आधारशिला हैं। विश्व भर में चिकित्सकों द्वारा दी जाने वाली कुल दवाइयों में इनकी हिस्सेदारी लगभग 80–90 प्रतिशत है और इसने आवश्यक दवाओं तक पहुँच बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यद्यपि जेनेरिक दवाइयाँ पैकेज, लेबल और निष्क्रिय अवयव की दृष्टि से भिन्न हो सकती हैं, लेकिन अध्ययनों से पता चला है कि ये अंतर उनके चिकित्सीय प्रभाव पर असर नहीं डालते हैं। खुराक, सुरक्षा, क्षमता, गुणवत्ता और लक्षित उपयोग के संदर्भ में जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं की समकक्ष हैं तथा उत्पादन और गुणवत्ता के कठोर मानकों का समान रूप से पालन करती हैं। पीएमबीजेपी केवल एक खुदरा–बिक्री कार्यक्रम नहीं हैय यह भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के संरचनात्मक सशक्तिकरण को दर्शाता है। यह इस साल के जनऔषधि सप्ताह के थीम में परिलक्षित होता है, जन औषधि सस्ती भी, भरोसेमंद भी, सेहत की बात, बचत के साथ, यह थीम लाखों लाभार्थियों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होती है। 18,000 से अधिक जनऔषधि केंद्रों के तेजी से बढ़ते नेटवर्क के माध्यम से, योजना ने सुनिश्चित किया है कि दवाइयाँ बाजार दरों की तुलना में 50 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक की कम कीमतों पर उपलब्ध हों और सभी सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों को समर्थन प्रदान करती हों। क्षेत्र सर्वेक्षणों से पता चला है कि लाभार्थी लागत बचत और दवाइयों तक बेहतर पहुँच की सराहना करते हैं। योजना का पैमाना इसके उत्पाद संग्रह से भी परिलक्षित होता है। जनऔषधि 2,110 दवाओं और 315 सर्जिकल उत्पादों का विस्तृत संग्रह पेश करता है, जो 29 विभिन्न चिकित्सीय क्षेत्रों को शामिल करती है। भारतीय औषधि एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई) के प्रत्यक्ष देखरेख में, संग्रह का विस्तार एक गतिशील, डेटा–संचालित प्रक्रिया है, जिसमें बाजार विश्लेषण, हितधारकों की भागीदारी और एक समर्पित विशेषज्ञ समिति की कठोर निगरानी शामिल हैं। इससे सुनिश्चित होता है कि योजना देश की बदलती स्वास्थ्य आवश्यकताओं और औषधीय मांगों के अनुरूप विकसित होती रहे।

कठोर नियामक निरीक्षण के साथ, भारतीय दवा कंपनियां 200 से अधिक देशों के लिए भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता बन गई हैं, जिसमें अमेरिका, यूके और यूरोपीय संघ जैसे अत्यधिक विनियमित बाजार भी शामिल हैं। भारतीय दवा कंपनियां लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और पूर्वी यूरोप जैसे उभरते बाजारों में भी विस्तार कर रही हैं। यह उद्योग जैविक दवाओं के समान दवाओं (बायोसिमिलर), जैविक दवाओं के जेनेरिक प्रतिरूपों पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है, साथ ही जटिल जेनेरिक और विशेष दवाओं का उत्पादन करने के लिए अनुसंधान और विकास में भी अधिक निवेश कर रहा है। ये दूरदर्शी कार्यक्रम भारत को न केवल एक वैश्विक उत्पादन केंद्र के रूप में, बल्कि किफायती दवाओं के क्षेत्र में भविष्य के नवाचार अग्रणी देश के रूप में भी स्थापित करते हैं। गुणवत्ता बनाम मूल्य पर बहस कभी–कभी सार्वजनिक धारणा को प्रभावित करती है। एक बहु–स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन व्यवस्था के माध्यम से,पीएमबीजेपी ने इस मिथक को प्रभावी ढंग से तोड़ दिया है कि किफायती होना निर्माण मानकों में समझौते का संकेत देता है। दवाइयाँ डब्ल्यूएचओ–जीएमपी प्रमाणित निर्माताओं से खरीदी जाती हैं, जो वैश्विक उत्पादन मानकों का पालन सुनिश्चित करती हैं। नियम निर्धारित करते हैं कि फार्मेसी की शेल्फ तक पहुंचने से पहले दवा के हर बैच का राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा स्वीकृत प्रयोगशालाओं में सख्त सत्यापन होना आवश्यक है। ये दवाइयाँ औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के नियमों का पालन करती हैं और ब्रांडेड विकल्पों के सुरक्षा और प्रभावशीलता मानकों के अनुरूप हैं। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खरीद से पहले सावधानीपूर्वक समीक्षा की जाती है और खरीद के बाद प्रयोगशाला में परीक्षण किया जाता है। परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी, पीएमबीआई नियमित रूप से दवाओं की गुणवत्ता की निगरानी और समीक्षा करती है, ताकि स्थापित विनियमों के पालन में कोई कोताही न होना सुनिश्चित किया जा सके। एक आईटी–संचालित वितरण नेटवर्क, जिसे पांच अत्याधुनिक भंडार गृहों और देशभर के में 41 विशेष वितरकों का समर्थन प्राप्त है, ने सुनिश्चित किया है कि आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के खिलाफ सुदृढ़ बनी रहे। तीन स्तंभों – पहुँच, गुणवत्ता और सस्ती कीमत – पर ध्यान केंद्रित करके, पीएमबीजेपी ने लाखों लोगों के चिकित्सा खर्च को काफी हद तक कम कर दिया है। निरंतर संस्थागत समर्थन, लोगों की बढ़ती जागरूकता और अवसंरचनात्मक सुधारों के साथ, हर जिले में जनऔषधि केंद्र का सपना अब दूर की आकांक्षा नहीं, बल्कि यह ठोस रूप ले चुका है और वास्तविकता के करीब है। शविकसित भारत ज्च2047 दृष्टि के तहत मुख्य ध्यान इस बात पर है कि हर किसी के लिए एक सुदृढ़, न्यायसंगत और किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बनाई जाए। इसमें बेहतर अस्पताल, कम चिकित्सा खर्च, उपचार तक आसान पहुंच और सस्ती दवाओं की उपलब्धता शामिल हैं। बहु–क्षेत्रीय सहयोगों के जरिये, पीएमबीजेपी ने यह साबित किया है कि सही संस्थागत दृष्टि के साथ, स्वास्थ्य सेवा उच्च गुणवत्ता युक्त और सार्वभौमिक रूप से सुलभ दोनों हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि यह परियोजना प्रगति करती रहे और किफायती स्वास्थ्य सेवा के वैश्विक मॉडल के रूप में अपनी स्थिति को निरंतर बनाए रखे।

राज्य महिला आयोग सदस्य ऋतु शाही ने जनसुनवाई मे सुनी महिलाओ की समस्या

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या।सोमवार को उ0प्र0 राज्य महिला आयोग सदस्य ऋतु शाही द्वारा सर्किट हाउस सभागार में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आई हुईं महिलाओं की समस्याओं एवं शिकायतों को गंभीरता से सुना गया।इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए गए। जन सुनवाई के दौरान सदस्य के सामने कुल 25 शिकायतें आईं।जिनमें पारिवारिक

विवाद, घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, भूमि विवाद, भरण–पोषण तथा अन्य सामाजिक समस्याओं से संबंधित प्रकरण प्रस्तुत किए गए।उन्होंने सभी मामलों को संवेदनशीलता के साथ सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को शिकायतों के त्वरित, निष्पक्ष एवं प्रभावी निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को न्याय दिलाना राज्य महिला आयोग की प्राथमिकता है और महिलाओं पर किसी भी प्रकार के उत्पीड़न या अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त शिकायतों पर गंभीरता से कार्यवाही करते हुए पीड़ित महिलाओं को शीघ्र न्याय दिलाना सुनिश्चित करें।बैठक के बाद उन्होंने दर्शन नगर में वन स्टाफ सेंटर का निरीक्षण किया।इस अवसर पर जिला प्रोबेशन अधिकारी अश्वनी कुमार पांडे,सीओ योगेंद्र,महिला थानाध्यक्ष आशा शुक्ला, वन स्टाफ सेंटर से सुधा वर्मा,स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर संदीप कुमार शुक्ला सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

जिला कार्यकारिणी में महिलाओं को तैंतीस प्रतिशत व सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व – गोविंद नारायण शुक्ला

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।भारतीय जनता पार्टी में जिला कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है।प्रदेश नेतृत्व के पर्यवेक्षक, प्रदेश महामंत्री व एमएलसी गोविंद नारायण शुक्ला ने सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों तथा वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर संगठन विस्तार और कार्यकारिणी गठन को लेकर विचार–विमर्श किया।प्रदेश महामंत्री व एमएलसी गोविंद नारायण शुक्ला ने कहा कि भाजपा संगठन में सभी वर्गों और समाज के हर तबके को सम्मानजनक भागीदारी देने की परंपरा रही है। उन्होंने बताया कि नई

कार्यकारिणी में महिलाओं को कम से कम 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, साथ ही सामाजिक और अनुसूचित वर्ग के कार्यकर्ताओं को भी समुचित स्थान सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि संगठन और अधिक मजबूत व व्यापक बन सके।जिला प्रभारी मिथिलेश त्रिपाठी ने कहा कि कार्यकारिणी गठन की प्रक्रिया संगठन की रीति–नीति के अनुरूप चल रही है और इसमें अनुभवी तथा सक्रिय कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा का लक्ष्य संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक सशक्त बनाना है।जिलाध्यक्ष राधेश्याम त्यागी ने बताया कि नई जिला कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, कोषाध्यक्ष, कार्यसमिति सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य, मीडिया प्रभारी, सोशल मीडिया प्रभारी और आईटी संयोजक सहित विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। उन्होंने कहा कि संगठन में सभी वर्गों और समाज के लोगों को समुचित प्रतिनिधित्व देकर पार्टी को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा।बैठक में पूर्व सांसद लल्लू सिंह, विधायक रामचंद्र यादव, चंद्रभानु पासवान, अमित सिंह चौहान, जिला प्रभारी मिथिलेश त्रिपाठी, जिलाध्यक्ष राधेश्याम त्यागी, संजीव सिंह, अवधेश पाण्डेय बादल, सुनील तिवारी शास्त्री सहित अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

कर्तव्यों में लापरवाही पर सख्त हुए पुलिस अधीक्षक,लाइन बाजार थाना प्रभारी निलंबित

ब्यूरो प्रमुख

विश्व प्रकाश श्रीवास्तव जौनपुर,10 मार्च ।यूपी के जौनपुर में जिले में कानून–व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है। कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने और लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर लाइन बाजार थाना प्रभारी सतीश कुमार सिंह को मंगलवार को निलंबित कर दिया है।लाइन बाजार थाने से संबंधित कार्यप्रणाली को लेकर पिछले कुछ समय से लगातार शिकायतें मिल रही थीं। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी ने इसकी समीक्षा की और प्रथम दृष्टया लापरवाही सामने आने पर थाना प्रभारी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई कर दी। बीते एक सप्ताह में लाइन बाजार थाना अंतर्गत हुए हत्या और मारपीट के मामले को लेकर ये कदम उठाया गया है। एसएसपी कुंवर अनुपम सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ड्यूटी में कोताही और अनुशासनहीनता किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जनता की सुरक्षा और कानून–व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी पुलिसकर्मी की कार्यप्रणाली में लापरवाही या शिकायत पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर सीधे बर्खास्तगी तक की कार्रवाई से भी पीछे नहीं हटेंगे। एसएसपी की इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। साथ ही जिले के सभी थानेदारों और पुलिसकर्मियों को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहें।

भारतीय कंपनियों को विस्तार करने में सक्षम बनायेगा इंडिया ग्रोथ समिट

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। वॉलमार्ट ने इंडिया ग्रोथ समिट 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। यह सम्मेलन भारतीय कंपनियों को घरेलू एवं वैश्विक स्तर पर विस्तार करने में सक्षम बनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। 7 मई, 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में सम्मेलन के दूसरे संस्करण का आयोजन होगा, जिसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई), डिजिटल–फर्स्ट ब्रांड्स, डायरेक्ट–टू–कंज्यूमर (डी2सी) सेलर्स और इनोवेटिव सप्लाई चेन कंपनियां एक मंच पर आएंगी और वॉलमार्ट के साथ मिलकर वैश्विक व्यापार में अपने लिए नए अवसर तलाशेंगी। वॉलमार्ट मार्केटप्लेस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मनीष जोनेजा ने कहा, 'वॉलमार्ट में हम कंपनियों को वैश्विक स्तर पर विकास करने में मदद देने के लिए उत्साहित हैं। इंडिया ग्रोथ समिट 2026 से इनोवेशन और सप्लायर्स एवं सेलर्स को वैश्विक बाजार में बढ़ने में मदद को लेकर हमारी प्रतिबद्धता दिखती है। हम कारोबार बढ़ाने और वैश्विक ग्राहकों तक पहुंचने के सफर में भारतीय उद्यमियों के साथ काम करने के लिए उत्साहित हैं।' वॉलमार्ट मार्केटप्लेस से जुड़ने और अंतरराष्ट्रीय ई–कॉमर्स में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की इच्छा रखने वाली भारतीय कंपनियां 23 अप्रैल, 2026 तक रजिस्ट्रेशन करा सकेंगी। यह सम्मेलन मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य होम टेक्सटाइल्स, कंज्यूमेबल्स, हेल्थ एवं वेलनेस, फूड, जनरल मर्चेंडाइज, ज्वेलरी, अपैरल, जूते खिलौने एवं स्टेशनरी जैसी प्रमुख कैटेगरी में निर्यात को बढ़ावा देना है।

इंडिया ग्रोथ समिट 2026 में एक एक्जीक्यूटिव सेशन आयोजित होगा, जिसमें उपस्थित लोगों को वॉलमार्ट के लीडर्स के विचारों को सुनने का मौका मिलेगा। इसके बाद क्यूरेटेड लर्निंग सेशंस भी आयोजित होंगे, जिनसे कारोबारियों को विकास करने, अपने परिचालन को आगे बढ़ाने, रिटेल सेक्टर से संबंधित प्रमुख इनसाइट्स पाने और ई–कॉमर्स के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जुड़ने में मदद मिलेगी। सम्मेलन में उपस्थित होने वालों को वॉलमार्ट मार्केटप्लेस पर रजिस्टर करने और क्रॉस–बॉर्डर ट्रेड के माध्यम से वैश्विक ग्राहकों तक पहुंचने का मौका मिलेगा। एक डेडिकेटेड रिसोर्स सेंटर के माध्यम से व्यक्तिगत स्तर पर एडवाइजरी सपोर्ट भी मिलेगा, जिससे वॉलमार्ट की कैटेगरी टीमों एवं संबंधित विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में कंपनियों को प्लेटफॉर्म ऑनबोर्डिंग, नियामकीय जरूरतों और क्रॉस–बॉर्डर ट्रेड में मदद मिलेगी।

2019 में अपनी लॉन्चिंग के बाद से वॉलमार्ट वृद्धि सप्लायर डेवलपमेंट प्रोग्राम ने भारत में 70,000 से ज्यादा एमएसएमई को प्रशिक्षित किया है। 2028 तक 1,00,000 एमएसएमई को प्रशिक्षित करने की योजना के साथ यह प्रोग्राम लगातार ऐसे संसाधन एवं प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है, जिससे कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों समेत अपनी पहुंच को विस्तार देने में मदद मिले। फ्लिपकार्ट पर 14 लाख से ज्यादा सेलर्स के साथ यह सम्मेलन उद्यमियों को अंतरराष्ट्रीय कारोबार के अवसरों को देखने का एक नजरिया भी देगा। साथ ही योग्य एमएसएमई को वैश्विक बाजार में कदम रखने और विकास के लिए जरूरी रास्ता बनाने में मदद करेगा।

इंडिया ग्रोथ समिट 2026 इनोवेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में भी काम करेगा, जिससे सप्लायर्स को अत्याधुनिक रिटेल टेक्नोलॉजी, उत्पादों को लेकर बदलती मांग और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकास के लिए जरूरी टूल्स तक जल्दी पहुंच मिल सकेगी। यह पहल मेक्सिको, चिली, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका में वॉलमार्ट के सफल वैश्विक प्रोग्रामों से प्रेरित है। इन देशों में वॉलमार्ट के प्रोग्राम से स्थानीय सप्लायर्स को वॉलमार्ट के ग्लोबल नेटवर्क में सुगमता से इंटीग्रेट होने का मौका मिला है।

चुने गए आवेदकों को नोटिफाई किया जाएगा और व्यक्तिगत रूप से सम्मेलन में आने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उनके पास वॉलमार्ट की लीडरशिप टीम और देशभर से डोमेन एक्सपर्ट्स एवं समान कारोबार करने वालों के साथ संपर्क स्थापित करने, महत्वपूर्ण इनसाइट्स पाने एवं वैश्विक स्तर पर अपने सफर को गति देने का मौका मिलेगा।

कमर्शियल व घरेलू गैस सिलेंडर न मिलने के चलते शहर से लेकर गांव तक लोग परेशान

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या।अमेरिका–ईरान युद्ध के बीच घरेलू व कमर्शियल गैस सिलेंडर पर संकट गहरा गया है। जिसका असर शहर से लेकर गांव तक दिखाई दे रहा है।इस समय सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को हो रही है जिनके घरों पर सिलेंडर कुछ ही दिनों के लिए शेष बचा हुआ है और उन लोगों के सामने और समस्या है जिनके घरों पर सिलेंडर खत्म हो गया है। इसके साथ ही साथ शहर के कई रेस्टोरेंट,होटल, कैंटीन,ठेलों वालों के लिए भी यह समस्या गंभीर बनी हुई है। इन प्रतिष्ठानों का संचालन करने वाले कई संचालकों का यह भी मानना है कि कमर्शियल सिलेंडर के न उपलब्ध होने से उनका धंधा लगभग चौपट होने जा रहा है और कई प्रतिष्ठान बंद होने के कगार पर हैं।वही गैस एजेंसी ऊपर लंबी चौड़ी फिर भी देखी जा रही है लेकिन गैस की आपूर्ति लगभग लगभग समाप्ति पर है जिसके चलते लोगों को बैरंग खाली सिलेंडर ही लेकर वापस आना पड़ रहा है।गैस की किल्लत से आम लोगों का किचन भी प्रभावित हो रहा है।गैस एजेंसी पर पहुंचे पुरुष और महिला ग्राहकों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई।उपभोक्ताओं का कहना है कि पहले से महंगाई से परेशान गरीबों पर और बोझ डाला जा रहा है।कई लोगों ने कहा कि रसोई चलाना अब और मुश्किल हो जाएगा।वही गैस बुकिंग के नियम भी बदल गये है।जब गैस उपभोक्ता सिलेंडर लेने के लिए अपने–अपने संबंधित गैस एजेंसियों के पास पहुंचे तो वहां पर कर्मियों द्वारा यह बताया गया कि अभी सिलेंडर नहीं है।जबकि कुछ गैस उपभोक्ताओं ने यह भी कहा कि शासन के ढुलमुल रही रवैया के चलते और अचानक घरेलू व कामर्शियल सिलेंडरों की

कीमतों में अत्यधिक बढ़ोतरी के चलते गैस एजेंटीयों ने अपने–अपने यहां सिलेंडरों को डंप कर लिया है और यहां तक की ब्लैक में भी सिलेंडर बेच रहे है। गैस उपभोक्ताओं का मानना है कि आने वाले वर्ष 2027 की विधानसभा चुनाव में इसका गंभीर परिणाम शासन को भुगतना पड़ेगा।मंगलवार को गैस सिलेंडर उपभोक्ता कई एजेंसियों प गैस सिलेंडर लाने के लिए गए लेकिन वहां पर उन्हें निराशा ही मिली। वहीं जिला पूर्ति अधिकारी बृजेश कुमार मिश्रा ने बताया घरेलू सिलेंडर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है किसी को घबराने की बात नहीं है सभी को सिलेंडर मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा हां कुछ दिक्कत कमर्शियल सिलेंडर को लेकर है। इस समस्या को भी शीघ्र ही दूर कर दिया जाएगा।

शिक्षा, समानता एवं सामाजिक परिवर्तन की प्रेरणा है सावित्री बाई फुले : प्रो हरिओम त्रिपाठी

ब्यूरो प्रमुख

विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,10 मार्च । यूपी के जौनपुर स्थित वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, महान समाज सुधारक एवं नारी शिक्षा की अग्रदूत सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि के अवसर पर मंगलवार को पुष्पांजलि कार्यक्रम एवं विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. वंदना सिंह की प्रेरणा से आर्यभट्ट सभागार, प्रो. राजेन्द्र सिंह (रज्जू भैया) संस्थान में आयोजित हुआ। इस अवसर पर शिक्षकों, अधिकारियों एवं विद्यार्थियों ने सावित्रीबाई फुले के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी और उनके महान योगदान को स्मरण किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता तिलकधारी पी.जी. कॉलेज, जौनपुर के प्रख्यात शिक्षाविद् प्रो. हरिओम त्रिपाठी ने "सावित्रीबाई फुलेरू भारतीय महिला शिक्षा की अग्रदूत" विषय पर व्याख्यान देते हुए कहा कि सावित्रीबाई फुले ने ऐसे समय में महिलाओं की शिक्षा का अलख जगाया, जब समाज में महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। उन्होंने अपने पति महात्मा ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर समाज में शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय की मजबूत नींव रखी। उन्होंने कहा कि सावित्रीबाई फुले का जीवन साहस, संघर्ष और समाज सेवा का प्रेरणादायी उदाहरण है, जो आज भी नई पीढ़ी को शिक्षा और समानता के लिए प्रेरित करता है। परीक्षा नियंत्रक डॉ. विनोद कुमार सिंह ने कहा कि सावित्रीबाई फुले केवल एक शिक्षिका ही नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की सशक्त प्रतीक थीं। उन्होंने अपने अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प से समाज में महिलाओं तथा वंचित वर्गों के लिए शिक्षा के द्वार खोले। उनके विचार आज भी समाज को प्रगतिशील और समतामूलक दिशा प्रदान करते हैं। शिक्षा संकाय के संकायाध्यक्ष प्रो. अजय दुबे ने कहा कि सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम बनाया। कार्यक्रम के संयोजक एवं अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रो. प्रमोद कुमार यादव ने सभी अतिथियों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन महान व्यक्तित्वों के आदर्शों को नई पीढ़ी तक पहुँचाने का सशक्त माध्यम होते हैं। उन्होंने कहा कि सावित्रीबाई फुले का जीवन हमें शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय के मूल्यों को आत्मसात करने की प्रेरणा देता है। कार्यक्रम का संचालन डॉ. नितेश जायसवाल ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉ. सुनील कुमार ने प्रस्तुत किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के शिक्षकगण एवं बड़ी संख्या में छात्र–छात्राएँ उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन सावित्रीबाई फुले के आदर्शों को आत्मसात करने के संकल्प के साथ हुआ।

भीम आर्मी जिलाध्यक्ष की टिप्पणी से आहत सवर्ण समाज आर्मी ने डीएम को सौंपा ज्ञापन

ब्यूरो प्रमुख

विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर, 10 मार्च । उत्तर प्रदेश के जौनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर में मंगलवार को सर्वण आर्मी के प्रदेश सचिव प्रवीण तिवारी के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष द्वारा बदलापुर विधायक रमेश चंद्र मिश्रा पर की गई कथित अमर्यादित टिप्पणी को लेकर कार्रवाई की मांग की। प्रदेश सचिव प्रवीण तिवारी ने बताया कि खुटहन थाना क्षेत्र के कुशहा गांव निवासी अनुसूचित जाति के युवक राजीव उर्फ रज्जू की मौत पिटाई से नहीं, बल्कि फेफड़ों में संक्रमण के कारण हुई है। उन्होंने कहा कि रविवार को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। शाहगंज क्षेत्राधिकारी अजीत सिंह चौहान ने भी इस संबंध में जानकारी दी है। तिवारी ने आरोप लगाया कि इस मामले में भीम आर्मी की ओर से सवर्ण समुदाय के लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस दौरान पुलिस प्रशासन के सामने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए बदलापुर के वर्तमान विधायक रमेश चंद्र मिश्रा के खिलाफ भी टिप्पणी की गई, जिससे सवर्ण समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने कहा कि यदि इस मामले में कोई दोषी है तो उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन निर्दोष लोगों को फंसाना उचित नहीं है। ऐसा करने से जिले में सामाजिक सौहार्द और कानून–व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। प्रवीण तिवारी ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि को जाति या धर्म के आधार पर निशाना बनाना गलत है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की जाए, ताकि जिले में अमन–चैन और सामाजिक सौहार्द बना रहे।

छत से गिरकर 2 वर्षीय बच्चे ने तोड़ा दम,परिवार में मचा कोहराम

ब्यूरो प्रमुख

विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,10 मार्च । यूपी के जौनपुर स्थित मछलीशहर कोतवाली क्षेत्र के कृपाशंकर नगर मोहल्ले में मंगलवार को एक हृदयविदारक घटना सामने आई। यहां छत से गिरने से 2 वर्षीय मासूम अयांश जायसवाल की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और पूरे मोहल्ले में शोक की लहर दौड़ गई। कृपाशंकर नगर निवासी सोनू जायसवाल का पुत्र अयांश मंगलवार दोपहर अपनी दादी के पीछे–पीछे छत पर चला गया था। दादी छत पर कपड़े डालने में व्यस्त थीं। इसी दौरान खेलते–खेलते अयांश पास की बाउंड्री पर चढ़ गया। अचानक संतुलन बिगड़ने से वह बगल की छत पर जा गिरा। गिरने से उसके सीने और पेट में गंभीर चोटें आ गईं। परिजन आनन–फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मछलीशहर ले गए, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। लेकिन जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मासूम को मृत घोषित कर दिया। मासूम की मौत से परिवार का रो–रोकर बुरा हाल है।

शेष बची हुई देशी मदिरा व कम्पोजिट दुकानों के आवंटन के लिए आबकारी विभाग ने शुरू की ई–लश्वटरी प्रक्रिया

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या। जिले मे शेष बची हुई देशी मदिरा और कम्पोजिट दुकानों के आवंटन के लिए आबकारी विभाग ने ई–लॉटरी प्रक्रिया शुरू कर दी है।यह जानकारी देते हुए जिला आबकारी कार्यालय के मुताबिक यह प्रक्रिया जनपद में शेष बची हुई और अव्यवस्थित दुकानों के लिए अपनाई जा रही है।ई–नवीनीकरण के बाद जनपद में देशी मदिरा की कुल 8 और कम्पोजिट श्रेणी की 1 दुकान बची हुई है। इन दुकानों के व्यवस्थापन के लिए ई–लॉटरी का पहला चरण आज, 10 मार्च से शुरू होगा।देशी मदिरा की दुकानों में चौक (शॉप आईडी–15188), देवकाली (शॉप आईडी–15339), नाका – सिंह ऑटोमोबाइल भारत पेट्रोल पम्प के निकट (शॉप आईडी–15718), मोदहा (शॉप आईडी–15297), वार्ड संख्या–44 सुभाष नगर (शॉप आईडी–35750), गोसाईगंज (शॉप आईडी–15628), कनावां (शॉप आईडी–21494) और मिटौरा (शॉप आईडी–16232) शामिल हैं। कम्पोजिट श्रेणी की धर्मगंज (शॉप आईडी–38304) दुकान भी इसी प्रक्रिया से आवंटित की जाएगी।इच्छुक आवेदक 10 मार्च 2026 को दोपहर 12 बजे से 17 मार्च 2026 को दोपहर 12 बजे तक ई–लॉटरी पोर्टल https://exciseelotteryup-upsdc-gov-in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आबकारी विभाग ने स्पष्ट

यूपी बोर्ड कॉपियों के मूल्यांकन के दौरान,मोबाइल प्रतिबंधित, डिजिटल सूचना साझा करने पर होगी एफआईआर

ब्यूरो प्रमुख

विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,10 मार्च । यूपी के जौनपुर में यूपी बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 18 मार्च से शुरू होगा। जौनपुर में, जिला विद्यालय निरीक्षक (क्प्ै) राकेश कुमार ने मूल्यांकन केंद्रों के निर्धारण के साथ–साथ प्रक्रिया को और सख्त बनाने के लिए नए नियम जारी किए हैं।इस संबंध में मंगलवार को देश की उपासना ब्यूरो से बात करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार सिंह ने बताया कि मूल्यांकन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए केंद्रों पर विशेष डिजिटल पाबंदी लागू की गई है। इस बार मूल्यांकन केंद्र के भीतर मोबाइल फोन या किसी भी

इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। शिक्षकों और अन्य कर्मियों के फोन मुख्य द्वार पर टोकन व्यवस्था के साथ जमा कराए जाएंगे। यदि कोई शिक्षक मूल्यांकन कार्य से अनुपस्थित रहता है या ड्यूटी से जी चुराता है, तो उसके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, मूल्यांकन कार्य की गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य है। किसी भी सूचना को मौखिक, लिखित या सोशल मीडिया (डिजिटल) प्लेटफॉर्म पर साझा करना अपराध माना जाएगा और ऐसा करने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। डीआईओएस ने निर्देश दिया है कि गणित और विज्ञान जैसे विषयों में परीक्षार्थियों को स्टेप मार्किंग का लाभ दिया जाए। इसका अर्थ है कि यदि पूरा सवाल सही नहीं है, तो भी सही किए गए स्टेप्स के लिए अंक मिलेंगे। साथ ही, भाषा की त्रुटियों पर केवल भाषा के विषयों में ही अंक काटे जाएंगे। अन्य विषयों में परीक्षकों को उदार दृष्टिकोण अपनाने के लिए कहा गया है। मूल्यांकन कार्य में लगे शिक्षकों के लिए एक राहत की बात यह है कि उनका पारिश्रमिक कार्य संपन्न होने के 15 दिनों के भीतर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

पंखे से फांसी लगाकर युवक ने दिया जान,पत्नी के मरने के बाद नशे में रहता था युवक

ब्यूरो प्रमुख

विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,10 मार्च। यूपी के जफराबाद थाना क्षेत्र के बैजाबाद गांव निवासी एक युवक ने सोमवार की देर रात को पंखे से साड़ी का फंदा बनाकर फांसी लगाकर अपनी जान दे दिया।मंगलवार की सुबह जानकारी होते ही कोहराम मच गया। उक्त गांव निवासी सूरज चौहान पुत्र बाबूराम चौहान की डेढ़ वर्ष पहले शादी हुई थी।वह पत्नी के साथ मुम्बई रहकर रोजी रोटी कमाता था।दो माह पूर्व उसकी पत्नी ने मुम्बई में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया था।उसका अंतिम संस्कार करने के बाद सूरज मुंबई से घर आकर रहने लगा।सोमवर की रात को सूरज चौहान खाना खाकर अपने कमरे में सोने चला गया।सुबह वह जब नही उठा तो परिजन दरवाजा के अंदर देखे।जहा पर सूरज पंखे से साड़ी के सहारे फंदा बनाकर आत्महत्या कर लिया था।उसने बेड पर स्टूल रखकर घटना को अंजाम दिया।उसे मृत देखकर पूरे परिवार में रोना पीटना मच गया।लोगों ने घटना की जानकारी थानाध्यक्ष श्रीप्रकाश शुक्ल को दिया। फोर्स मौके पर पहुंच शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।बताया जाता है पत्नी की मौत के बाद वह अधिक शराब का नशा करने लगा था।वह अक्सर शराब पीकर कहता कि उसकी पत्नी की आत्मा उसे परेशान कर रही है।मृतक सूरज अपने चार भाइयों में सबसे छोटा था।थानाध्यक्ष श्री शुक्ल ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे के लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

रोटी बैंक वाराणसी की "रोटी से रोजगार" पहल के तहत दिव्यांग युवक को मिली नई शुरुआत

देश की उपासना ब्यूरो

वाराणसी। समाजसेवा के क्षेत्र में सक्रिय रोटी बैंक वाराणसी द्वारा "रोटी से रोजगार" पहल के अंतर्गत 80: दिव्यांग युवक प्रिंस कुमार को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से वजन करने वाली मशीन प्रदान की गई। प्रिंस कुमार पहले घाटों पर बैठकर भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि वे भिक्षा नहीं बल्कि मेहनत के बल पर स्वाभिमान के साथ जीवन जीना चाहते हैं। उनकी इसी सकारात्मक सोच और दृढ़ इच्छाशक्ति को देखते हुए रोटी बैंक वाराणसी की टीम ने उन्हें वजन करने वाली मशीन देकर रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सकें। रोटी बैंक वाराणसी की इस पहल का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को केवल भोजन उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि उन्हें रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना भी है। इस अवसर पर रोटी बैंक के अध्यक्ष रौशन पटेल, रिंकू सेठ, रजत श्रीवास्तव तथा अभिषेक कुमार उपस्थित रहे।

सड़क हादसे मे युवक की दर्दनाक मौत, दूसरा घायल

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या। लखनऊ–गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच–27) पर सोमवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया।हादसा बूथ नंबर–4 के पास उस समय हुआ, जब पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी।रामनगरी जा रहे यातायात उप निरीक्षक कृष्ण कुमार सिंह ने तत्काल घटना की सूचना अयोध्या कोतवाली पुलिस को दिया।पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए ट्रामा सेंटर भेजा।मिली जानकारी के मुताबिक बहराइच जिले के रानी थाना क्षेत्र के कटहरी गांव निवासी 26 वर्षीय मोहम्मद कामिल अयोध्या में रहकर कैटरिंग का काम करते थे।सोमवार दोपहर वह अपने मित्र रिजवान निवासी रतिया, थाना कैंट के साथ बाइक से अयोध्या की ओर जा रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक बूथ नंबर–4 के पास पहुंची,पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी।टक्कर इतनी तेज थी कि मोहम्मद कामिल डंपर के नीचे आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।वहीं बाइक चला रहे रिजवान गंभीर रूप से घायल हो गए।आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

लोक अदालत का आयोजन 14 मार्च को

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के अनुपालन में जनपद न्यायाधीशध्अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अयोध्या के निर्देशानुसार 'आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 मार्च (द्वितीय शनिवार) को किया जायेगा।राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों को आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराया जा सकता है।राष्ट्रीय लोक अदालत में निम्नांकित विषयों से संबन्धित वादों का निस्तारण किया जायेगा।प्रिलिटीगेशन स्तर के विवाद– धारा 138 पराक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट), बैंक वसूली वाद, श्रम विवाद वाद, विद्युत एंव जलवाद बिल (अशमनीय छोड़ कर) व अन्य (आपराधिक शमनीय, पारिवारिक एवं अन्य व्यवहार वाद),न्यायालय में लम्बित वाद(जो नेशनल जुडीशियल डाटा ग्रिड पर प्रदर्शित हो),आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 पराक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट), बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाऐ, श्रम विवाद वाद, विद्युत एंव जलवाद बिल (अशमनीय छोड़ कर), पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, सर्विस मैटर से संबंधित वेतन, भत्ता और सेवानिवृत्ति लाभ के मामले, राजस्व वाद, जो जनपद न्यायालय और उच्च न्यायालय में लम्बित हों व अन्य सिविल वाद (किरायेदारी, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा वाद, विशिष्ट अनुतोष वाद) आदि का निस्तारण होगा।उक्त जानकारी रंजिनी शुक्ला सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अयोध्या ने दी है।

अवैध रूप से संचालित कोचिंग को डीआईओएस ने बंद करने का दिया निर्देश

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या।डीआईओएस डॉक्टर पवन कुमार तिवारी ने अवैध रूप से संचालित कोचिंग को बंद करने का सख्त निर्देश कोचिंग संचालक को दिया है।इस संबंध मे डीआईओएस डॉक्टर पवन कुमार तिवारी ने बताया इस क्षेत्र के शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत की गई थी कि जिले के तारुन विकास खंड क्षेत्र में मजरे सराय शेख स्थित ओम शिव कोचिंग क्लासेस पिछले 10 वर्षों से अवैध रूप से संचालित हो रही है।इसके साथ ही साथ इस कोचिंग में बिना मान्यता के अवैध रूप से कक्षा 1 से 12 तक शिक्षण कार्य भी हो रहा है।शिकायतकर्ता द्वारा जांच कराए जाने पर यह कोचिंग बंद मिला। बताया कि अगर यह कोचिंग दोबारा खुली पाई गई तो कोचिंग संचालक के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाएगी।

घरेलू गैस सिलेंडर आपूर्ति की व्यवस्था बीकापुर क्षेत्र मे चरमराई

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या। घरेलू गैस सिलेंडर आपूर्ति की व्यवस्था करीब–करीब पूरे जनपद में चरमरा गई है। बीकापुर में भी अमर रसोई पॉइंट कार्यालय के सामने उपभोक्ताओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है। नाराज उपभोक्ताओं ने वितरक पर मनमाने ढंग से घरेलू गैस सिलेंडर वितरित करने का आरोप लगाया है। तो वहीं बीकापुर के पूर्ति निरीक्षक श्री नारायण यादव ने घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति के बाबत जवाबदेही से किनारा करते हुए जानकारी के लिए जिला पूर्ति अधिकारी से संपर्क करने की बात कही है। दूसरी ओर क्षेत्र में होम डिलीवरी की व्यवस्था रोक दी गई है तस्वीरें बयां कर रही हैं किस तरह से दूर दराज से आए उपभोक्ता खुले मैदान में घंटों लंबी लाइनों में लगकर अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। उपभोक्ताओं का यह भी आरोप है कि चार–पांच दिन पहले बुकिंग करने के बाद भी उन्हें एक अदद गैस सिलेंडर प्राप्त करने के लिए कड़ी मस्कट का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल वितरक द्वारा किसी भी प्रकार की किल्लत की स्थिति से इनकार किया गया है। तथा सभी को नियमानुसार वितरण व्यवस्था प्रदत्त करने की बात कही गई है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को भी हस्तक्षेप करना पड़ा है।

डीआईओएस ने ग्राम विद्यालय इंटर कालेज कोदैला के प्रधानाचार्य का एक माह का वेतन रोकने का दिया निर्देश

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या। कार्य के प्रति लापरवाही बरतने के चलते डीआईओएस डॉ पवन कुमार तिवारी ने ग्राम विद्यालय इंटर कालेज कोदैला के प्रधानाचार्य धर्मेंद्र कुमार सिंह का एक माह का वेतन रोकने के साथ–साथ कार्यालय में स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है।बताते चलें कि ऑनलाइन शिकायत सन्दर्भ संख्या 40017725062858 अनिल कुमार ग्राम ककराही ब्लॉक तारुन तहसील बीकापुर जनपद अयोध्या के द्वारा शिकायत की गयी थी कि इनकी पुत्री आर्या ग्राम विद्यालय इण्टर कालेज कोदेला अयोध्या में कक्षा 9 की छात्रा है।उक्त विद्यालय के छात्र पंजिका में इनके पुत्री की जन्म तिथि संधोशित करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया था। आपको प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने हेतु कार्यालय से प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराया गया।इसके साथ साथ तथा शिकायत कर्ता से भी अंकित मोबाइल नम्बर पर जानकारी ली गयी जिसमें शिकायत कर्ता ने बताया था कि प्राथमिक विद्यालय ककराही अयोध्या से वर्ष 2022 में कक्षा–5 उत्तीर्ण किया विद्यालय के प्रवेश पंजिका क्रमांक संख्या 670 में जन्मतिथि 19.03.2012 अंकित है। जिसकी टी०सी० प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न किया गया है।एवं छात्रा के जन्म प्रमाण पत्र में भी जन्म तिथि 19.03.2012 है यह भी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किया गया है।प्रकरण की जाँच परीक्षण के क्रम में यह तथ्य संज्ञान में आया कि आवेदक की पुत्री आर्या जो आपके संस्था में कक्षा 9 की छात्रा है।आवेदक द्वारा प्रस्तुत टी०सी० प्रमाण पत्र में प्राधनिक स्तर से जारी हुई थी। प्राथमिक स्तर से जारी टी०सी० में त्रुटिवश वास्तविक जन्म तिथि 19.03.2012 से स्थान पर त्रुटिपूर्ण 19.09.2012 दर्ज हो गयी थी। जिसके सुधार हेतु आवेदक ने पुन प्राथमिक स्तर से जारी टी०सी० प्रमाण पत्र की संशोधित मूलप्रति 100 रूपये का शपथ पत्र, एवं छात्रा का जन्म प्रमाण पत्र प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया गया कि वास्तविक संशोधित अभिलेखों के आधार पर मित्रा की जन्म तिथि को सही–सही संशोधित कर दिया।पोर्टल पर निस्तारण तिथि 21.09.2025 थी जिसके सम्बन्ध में आख्या अपलोड करने के पूर्व पुन आपको विस्तृत रूप से अवगत कराते हुए बताया गया कि आवेदक के द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का परीक्षण करते हुए वास्तविक संशोधित जन्म तिथि के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही विद्यालय स्तर से सम्पादित कर दी जाये तथा यही आख्या पोर्टल पर अपलोड की गयी थी सुसंगत अभिलेखों के आधार पर संस्था प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालय स्तर से सुधार किया जायेगा। प्रकरण निस्तारण होने के पूर्व जिलाधिकारी महोदय अयोध्या के कार्यालय एवं अधोहस्ताक्षरी द्वारा शिकायत कर्ता के द्वारा अकित मोवाइल नम्बर पर फीड बैंक प्राप्त किया गया जिसमें आवेदक ने अवगत कराया आपसे कई बार–सम्पर्क करने के उपरान्त भी अद्यतन समस्या का समाधान नहीं किया गया, आवेदक निस्तारण से संतुष्ट नहीं है जिससे शिकायत सी श्रेणी में अन्दर्मित हो गयी है।शिकायत का निस्तारण अद्यतन ने होने के उच्चाधिकारियों द्वारा असंतोष व्यक्त किया जा रहा है। प्रश्नगत शिकायत के निस्तारण के सम्बन्ध में पुन अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 09.03.2026 को समस्या का समाधान करते हुए तत्काल निस्तारित करने हेतु निर्देशित किया गया। कॉलेज के प्रधानाचार्य व उनके सहायक द्वारा कार्य में रुचि न लेने के चलते लापरवाही प्रतीत होता है जिसके चलते डीआईओएस ने प्रधानाचार्य का मार्च माह का वेतन रोकते हुए लापरवाही बरतने के मामले मे प्रधानाचार्य को तय सीमा के अंदर स्पष्टीकरण देने को कहा है।

महिला एसओ आशा शुक्ला ने एसआई श्वेता राठौर के साथ महिलाओ को किया जागरूक

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या। सोमवार को सीओ सिटी श्रीयेश त्रिपाठी की देखरेख मे महिला थानाध्यक्ष आशा शुक्ला के साथ महिला उप निरीक्षक श्वेता राठौर व अन्य महिला पुलिस कर्मियों ने महिला थाना परिसर मे महिलाओ व बेटियों को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के प्रति जागरूक किया।इस मौके पर उन्होंने मिशन शक्ति अभियान फेज फाइव के तहत सुरक्षात्मक उपाय भी बताई।इस मौके पर उन्होंने महिलाओं तथा बालिकाओं को सुरक्षात्मक टिप्स की भी जानकारी देते हुए बताया कि जिससे कभी भी संकट के समय आप अपनी सुरक्षा कर सकती हैं।इस मौके पर उप निरीक्षक श्वेता राठौर ने बालिकाओं से कहीं।उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा महिलाओं तथा बालिकाओं के लिए जहां एक तरफ उनके विकास को लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला सशक्तिकरण सुकन्या समृद्धि योजना सहित एक से बढ़कर एक कई महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं। वहीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी केंद्र व राज्य सरकार कई योजनाएं चल रही हैं।इस मौके पर उन्होंने वहां पर मौजूद बालिकाओं को पंपलेट व बैनर पोस्ट के माध्यम से जानकारी देते हुए कहा कि अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना का अंदेशा हो तो बिना झिझक अपने नजदीकी पुलिस कर्मियों, महिला थाना तथा अपने परिजनों को फोन पर बताये।इस मौके पर उन्होंने विधवा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जिसमे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन एवं सुकन्या समृद्धि योजना और हेल्पलाइन नंबर के बारे में महिलाओं को जागरूक किया।इसके अलावा उन्होंने उन्हें किसी भी प्रकार की पुलिस सहायता हेतु विमेन पावर लाइन 1090, यूपी 112, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, चाइल्ड लाइन 1098, साइबर अपराध 1930 के बारे में बताया गया। बताया कि यह सभी नंबर आप लोग हमेशा याद रखें।इस मौके पर उनके अलावा महिला थाना परिसर मे तैनात अन्य पुलिस कर्मी मौजूद रही।

एडीएम सिटी योगानंद पाडे की अध्यक्षता मे बैठक सम्पन्न

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। मंगलवार को एडीएम सिटी योगानंद पांडे की अध्यक्षता में चौरासीकोसी, चौदहकोसी, पंचकोसी व रिंग रोड निर्माणध्प्रतिकार भुगतान तथा आवास विकास परिषद द्वारा संचालित योजनाओं के तहत भूमि अधिग्रहण की प्रगति के संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।बैठक में मुख्य रुप से चौरासीकोसी, चौदहकोसी व पंचकोसी परियोजनाओं के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण की वर्तमान स्थिति, प्रतिकार भुगतान की प्रगति तथा शेष प्रकरणों के निस्तारण की समीक्षा की गई।इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अधिग्रहण से संबंधित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित करते हुए पात्र किसानोंध्भूमि स्वामियों को प्रतिकार भुगतान की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कराई जाए,जिससे निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आए।समीक्षा के दौरान यह भी निर्देश दिया कि जिन प्रकरणों में कोई तकनीकी अथवा राजस्व संबंधी समस्या लंबित है,उन्हें आपसी समन्वय से शीघ्र हल करते हुए कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण कराया जाए। इस मौके पर परियोजनाओं की प्रगति की नियमित निगरानी करते हुए शासन के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। रिंग रोड निर्माण के संबंध में तहसील सोहावल एवं सदर उपजिलाधिकारी को निर्देश दिया गया कि कब्जा और भुगतान की प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण कराया जाए।आवास विकास परिषद को बक4 में अंश निर्धारण एवं अधिग्रहण की प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।बैठक में अपर जिलाधिकारी (भू.ध्आ.) कौशल कुमार, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) अनिरुद्ध कुमार सिंह,अपर जिलाधिकारी (वि.ध्रा.) अमित कुमार भट्ट सहित सभी उप जिलाधिकारी एवं अधिशासी अभियंता उपस्थित रहें।

आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड ने भारतीय सेना के साथ मओयू पर किया हस्ताक्षर

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या। वर्तमान में सेवा दे रहे सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को शैक्षणिक सहायता और कल्याणकारी लाभ उपलब्ध कराए जा सकें।इस घ्म ओ यू के तहत देशभर में स्कॉलरशिप और विशेष सुविधाएँ शामिल हैं, जो एईएसएल के किसी भी केंद्र में नामांकन करने वाले सेना से जुड़े विद्यार्थियों को प्रदान की जाएँगी।इसके लिए मंगलवार को टेस्ट प्रिपरेटरी सेवाओं में राष्ट्रीय अग्रणी एईएसएल ने भारतीय सेना के साथ घ्म ओ यू पर हस्ताक्षर किए हैं।जिसका उद्देश्य सेना के कर्मियों और उनके परिवारों के कल्याण को समर्थन देना है।इसमें वर्तमान में सेवा दे रहे सदस्य, सेवानिवृत्त सैनिक, गैलेंट्री पुरस्कार विजेता, दिव्यांग कर्मी तथा ड्यूटी के दौरान शहीद हुए सैनिकों के परिवार शामिल हैं।इस घ्म ओ यू के तहत, एईएसएल देशभर में स्थित अपने सभी केंद्रों और शाखाओं में प्रवेश लेने वाले भारतीय सेना के विद्यार्थियों को विशेष लाभ प्रदान करेगा।यह समझौता भारतीय सेना के कर्नल, सेरेमोनियल एंड वेलफेयर 3–4 और एईएसएल के डॉ. यश पाल, चीफ अकैडमिक एंड बिजनेस हेड, दिल्ली–एनसीआर द्वारा हस्ताक्षरित किया गया।यह घ्मओयू भारतीय सेना के कर्मियों और उनके परिवारों के कल्याण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, जिसमें देशभर के एईएसएल केंद्रों पर पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्तियाँ प्रदान करना भी शामिल है।सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी, ड्यूटी के दौरान शहीद हुए कर्मियों के बच्चों के लिए बाकी सभी फीस में 100% छूट है।20% से ज्यादा विकलांगता वाले कर्मियों और वीरता पुरस्कार पाने वालों के बच्चों के लिए 100: ट्यूशन फीस माफ है।सेवारत और रिटायर्ड कर्मियों के बच्चों के लिए 20: ट्यूशन फीस में छूट है, जो दूसरी स्कॉलरशिप घटाने के बाद लागू होगी।इन छात्रवृत्तियों के अलावा एईएसएल की पहले से चल रही स्कॉलरशिप योजनाएँ भी जारी रहेंगी, जिनका लाभ प्रवेश लेने की इच्छा रखने वाले सभी विद्यार्थियों को मिलता है। एईएसएल के एमडी और सीईओ श्री चंद्र शेखर गरिसा रेड्डी ने कहारू"एईएसएल में हमारा विश्वास है कि शिक्षा उज्जवल भविष्य की सबसे मजबूत नींव है। भारतीय सेना के साथ साझेदारी के माध्यम से हम अपने बहादुर सैनिकों के त्याग का सम्मान करते हुए उनके परिवारों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। स्कॉलरशिप, मेंटरिंग और काउंसलिंग के माध्यम से हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि हमारे वीरों के बच्चे अपनी पूरी क्षमता हासिल कर सकें और अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट नेतृत्व स्थापित करें।इस घ्म ओ यू की अवधि के दौरान, एईएसएल भारतीय सेना के कर्मियों के बच्चों को व्यापक मेंटरिंग और काउंसलिंग सहायता भी प्रदान करेगा।यह सहायता शैक्षणिक और करियर से जुड़ी सभी शंकाओं के समाधान के लिए वर्चुअल और फिजिकल दोनों माध्यमों से उपलब्ध होगी।हाल ही में, एईएसएल ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन (सीडब्ल्यूए) के साथ भी एक घ्म ओ यू किया है, जिसके तहत देशभर में सीआरपीएफ कर्मियों के बच्चों और परिवारों को शैक्षणिक सहायता, छात्रवृत्तियाँ और करियर मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा।आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड के बारे मेंएईएसएल भारत की प्रमुख टेस्ट प्रिपरेशन कंपनी है, जो विशेष रूप से मेडिकल (नीट) और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं (श्रम्म्) के साथ–साथ छज्ैम् और ओलंपियाड जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए व्यापक और प्रभावी सेवाएँ प्रदान करती है।एईएसएल का पूरे भारत में 415 से अधिक केंद्रों का नेटवर्क है, जिसमें 4,00,000 से अधिक वर्तमान में नामांकित विद्यार्थी शामिल हैं। पिछले 37 वर्षों में इसने मजबूत बाजार स्थिति और ब्रांड वैल्यू स्थापित की है। कंपनी का उद्देश्य छात्रों की वास्तविक क्षमता को न्दसवबा करना और उनके शैक्षणिक प्रयासों में सफलता सुनिश्चित करना है।एईएसएल छात्रों–केंद्रित दृष्टिकोण अपनाता है,यह समझते हुए कि हर छात्र अनोखा है और उसकी अलग जरूरतें हैं। इसमें उच्च योग्य और अनुभवी प्रशिक्षकों की टीम है, जो छात्रों को उनके सपने पूरे करने में मदद करने के लिए उत्साहित है।कंपनी के प्रोग्राम लचीले हैं और इसकी शिक्षण पद्धतियाँ नवीनतम तकनीकों पर आधारित हैं,ताकि छात्र अपनी परीक्षाओं के लिए पूरी तरह तैयार हो सकें।

कृपा शंकर वर्मा अध्यक्ष और प्रदीप कुमार यादव ब्लॉक मंत्री हुए निर्वाचित

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। मंगलवार को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ संबद्ध अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ,ब्लॉक मया जनपद अयोध्या का शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी एवं वार्षिक अधिवेशन हुआ।इस मौके पर निर्वाचन अधिकारी के रूप में डॉ सुरेश मौर्य , डॉ मनुजेश यादव वरिष्ठ उपाध्यक्ष, चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में रंजीत यादव ब्लॉक अध्यक्ष हैरिंगटनगंज, ने चुनाव निष्पक्ष और सुचिता पूर्ण रूप में संपन्न कराया।जिला अध्यक्ष अवधेश यादव, जिला मंत्री अशोक वर्मा,जिला कोषाध्यक्ष फूल चंद सरोज, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ मनुजेश यादव, जिला संयुक्त मंत्री अजय वर्मा, सहित पूरी जिला कार्यकारी ब्लॉक मया के शिक्षक अधिवेशन में मौजूद रही।निर्वाचन प्रक्रिया में ब्लॉक अध्यक्ष कृपा शंकर वर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राम राज,ब्लॉक मंत्री प्रदीप कुमार यादव, संयुक्त मंत्री अवधेश वर्मा, कोषाध्यक्ष पद पर सुनील वर्मा निर्वाचित हुए।अध्यक्ष पद के अलावा अन्य पदो पर निर्विरोध चुनाव हुआ।अध्यक्ष पद हेतु राजमन ने नामांकन किया।किन्तु कृपा शंकर वर्मा जी के समर्थन में उन्होंने अपना नाम वापस लिया। निर्वाचन के बाद जिला मंत्री अशोक वर्मा ने सभी शिक्षक पदाधिकारियों को पद और दायित्व की शपथ दिलाई, जिला कोषाध्यक्ष फूल चंद सरोज ने भी संबोधित किया, उक्त कार्यक्रम की अध्यक्षत मया के प्रधान अध्यापक चंद्र भान यादव ने किया, कार्यालय बीआरसी मया पर उक्त कार्यक्रम संपन्न हुआ।कार्यक्रम में जिला जीत वर्मा जिला मीडिया प्रभारी, मनोज यादव, देवेंद्र वर्मा, डॉ प्रेम कांत यादव,सत्यप्राश वर्मा, करम सिंह, राजमन, मनीष सरकार, संजय चौधरी,साधना तिवारी, श्यामविहारी यादव, अरुणकुमार, धर्मेंद्र कुमार, संजय चौधरी, प्रदीप मौर्य जिला संगठन मंत्री,चंद्रमणि वर्मा, सूरज प्रकाश, उमाशंकर, ब्लॉक संयोजक सोहावल, राम अंजोर,सहित तमाम शिक्षक साथी और शिक्षिका बहने मौजूद रही।

राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम पर एक दिवसीय प्रशिक्षण का हुआ आयोजन

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। मंगलवार को राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम पर एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय सभागार में किया गया।इस मौके पर डॉ प्रवीण मौर्य ने प्रतिभागियों को बचाव, उपचार, टीकाकरण एवं इलाज के बारे में विस्तृत जानकारी दिया।

कार्यक्रम मे जिला सर्विलांस अधिकारी पीसी भारती ने बताया कुत्ता, बंदर, जैकाल, सियार, के काटने पर केवल ब्ंजमहंतल –3 जायदा घाव वाले को ही रेबीज इम्यूनोग्लिबलिन इंजेक्शन लगेगा।डॉ आशुतोष श्रीवास्तव ने रेबीज वायरस के संक्रमण डॉग बाइट के कैटेगरी के बारे में बताया , डॉ अरविंद श्रीवास्तव जिला एपिडेमियोलॉजिस्टि ने रेबीज वेक्सीन की डोज कब कब लगना।उसके बारे एवं महीने में भेजे जाने वाली रेबीज रिपोर्ट के बारे में चर्चा की, ट्रेनिंग में डॉ बीएन यादव,डॉ दीपक पांडे एआरओ प्रवीण त्रिपाठी,डॉ सद्दाम खान एआरओ, कुलदीप सिंह डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि ने भाग लिया।

राजघाट पुल पर बदले जाएंगे जॉइंट और बेयरिंग

गोरखपुर, (संवाददाता)। राप्ती नदी पर स्थित राजघाट के पुराने पुल की मरम्मत का काम 15 मार्च के बाद शुरू होगा। इस दौरान पुल के खराब हो चुके जॉइंट और बेयरिंग बदले जाएंगे। इसके लिए 40 दिनों तक रूट डायवर्ट किया जाएगा। अभी तक बने प्रस्ताव के मुताबिक, पुल पर सड़क की आधी चौड़ाई में मरम्मत होगी और आधी से होकर छोटी गाड़ियों का आवागमन होता रहेगा। बड़े वाहन समानांतर दूसरे पुल से होकर गुजरेंगे। वर्ष 1965 में बने यानी 61 साल पुराने पुल के कई हिस्सों में दरारें मिलने के बाद पीडब्ल्यूडी (लोक निर्माण विभाग) ने जांच कराई। निरीक्षण में पाया गया कि पुल की कंक्रीट में दरारें आ चुकी हैं और जॉइंट के आसपास लगी बेयरिंग जर्जर हो चुकी हैं। इसके बाद मरम्मत कराने का निर्णय लिया है। मरम्मत का यह काम करीब 20 वर्ष बाद हो रहा है। केमिकल से दरारें भर दी गई हैं। अब मुख्य काम जॉइंट और बेयरिंग बदलने का होगा। मरम्मत के पूरा होने के बाद पुल की लोड टेस्टिंग भी की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पुल में अब कोई संरचनात्मक कमी नहीं है और वर्षों तक यातायात को सुचारू रूप से सहन कर सकता है। अधिशासी अभियंता अरविंद कुमार ने बताया कि बेयरिंग बदलने के लिए पुल पर चार चरणों में काम कराया जाएगा। एक लेन में काम होगा और दूसरी लेन में छोटी गाड़ियां आती–जाती रहेंगी। बड़े वाहनों को डायवर्ट करने की योजना है।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक **देश की उपासना**

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।